being combed to mop them up. So far 82 persons from Issac Swu's gang have been captured and 3 have been killed in 24 encounters and clashes. On our side, there has been only one casualty, namely, 1 officer wounded. Our Security Forces have so far recovered 60 weapons from this gang. These consist of one 60 mm mortar, one rocket launcher, one 7.62 mm LMG, 33 semiautomatic rifles, one 303 rifle. 11 sub-machine guns and 12 pistols. A substantial quantity of ammunition has also been recovered. Most of these weapons and ammunition are of Chinese origin.

Cases against those who have been captured are being examined on merits and appropriate action will be taken against them in accordance with the law.

Our Security Forces have throughout been working in close consultation with the Governor and the Government of Nagaland and receiving full-co-operation from the village guards and the civilian population. There have been a number of instances where villagers themselves have rounded up China returned Nagas and handed them over to the Security Forces along with weapons. The Village Guards have also been actively assisting the Security Forces and 9 members of Issac Swu's gang along with weapons were captured by them.

I am sure, the House would wish me to convey our appreciation of the commendable work done by our Security Forces as well as by the Village Guards and the civil population in the Nagaland, and congratulate the Government of Nagaland for the success of these operations. I have no doubt that we have been able to break the backbone of the misguided movement of those Nagas who had sought help and inspiration from foreign Powers. The success of our operations should enable the State Government to bring all the misguided elements to the path of peace and reason, and it is my hope that before long, normalcy would return to Nagaland and all the Nagas would be able to work for their progress and prosperity in accordance with our democratic Constitution and traditions.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Thirty-third Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): I beg to move :

> "That this House do agree with the Thirty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 31st March, 1969"

MR. SPEAKER : The question is :

> "That this House do agree with the Thirty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 31st March, 1969."

The motion was adopted.

DEMANDS FOR GRANTS-*Contd.*

Ministry of Irrigation and Power-*Contd.*

MR. SPEAKER : We have taken 1 hour 50 minutes, Still we have got 2 hours 10 minutes.

SHRI S. M. BANERJEE : May I suggest that the hon. Minister may intervene at 5 O'clock.

MR. SPEAKER : On Irrigation and Power one or two hon. members may like to speak. It is only to-day it is on the agenda. After Irrigation and Power, Andhra discussion comes. The Minister may begin the reply at 4 O'clock. He will take about 40 minutes. There will be no extension. By half an hour or 20 minutes we exceed normally.

Now Shri Ganga Reddy was speaking.

We adjourn for lunch and meet at 2 O'clock.

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

DEMANDS FOR GRANTS *Contd.*

Ministry of Irrigations and Power-*Contd.*

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Ganga Reddy may continue his speech.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने आप को भी पत्र द्वारा सूचित किया था, और मैं अपनी बात एक दो मिनट में खत्म कर दूंगा। मेरे क्षेत्र के मुंगेर शहर में पिछले दो महीनों में चार या पांच मर्तबा हिन्दू मुसलमानों के दंगे करवाये गये हैं और करीब करीब एक दर्जन मुसलमानों को कत्ल किया गया है। पुलिस वाले इस के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। जब बिहार में राष्ट्रपति का शासन था तब कई मर्तबा मैं ने गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेट्री और कलेक्टर सब को पत्र लिखे थे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि इस तरह की वार्ता की तरफ केन्द्रीय सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है। आखिरकार केन्द्रीय सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है। इसी तरह से बिहार के अन्दर पुरी के शंकराचार्य खुल्लम खुल्ला अस्पृश्यता का प्रचार करते हैं और अस्पृश्यता में विश्वास करते हैं। क्या अस्पृश्यता कानून की तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है? अगर शंकराचार्य जैसे आदमी को जेल में रक्खा जा सके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अस्पृश्यता के बारे में जो दकियानूसी विचार हैं वह खत्म हो जायेंगे। इस लिये इन दोनों बातों की तरफ गृह-मंत्री का ध्यान आप दिलायें कि मुसलमानों का कत्ल किया गया है, अस्पृश्यों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पुरी के शंकराचार्य को जेल में डाला जाय ताकि सारी दुनिया को पता लगे कि अस्पृश्यता के बारे में जो संविधान की धारा है, उस पर हमारा विश्वास है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : जब डा० कर्ण सिंह ने उस कांफरेंस का उद्घाटन किया था तब शंकराचार्य ने बयान दिया कि वेदशास्त्र जो है उसमें लिखा है कि हरिजन ज्यों का त्यों रहे। यह मैं ने होम मिनिस्ट्री पर बोलते हुए कहा था। लेकिन आज के अखबारों ने उस को टोटली नेगलेक्ट किया कि हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है। हम लोग आप का प्रोटेक्शन चाहते हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER : What can I do about it ? It would have been proper if the Hon. Member had pointed out the events in Monghyr yesterday at the time of Home Ministry's demands. These should have been brought to the notice of the Home Minister then.

श्री मधु लिमये : दो तीन दिन से फिर शुरू हो गये हैं। मैं सोच रहा था कि वह रुक जायेगा। नहीं तो मैं गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों के समय कहता।

MR. DEPUTY SPEAKER : That was the proper time.

श्री शशि भूषण (खारगोन): कटक (उड़ीसा) में मुसलमानों पर झूठा बम केस चलाया जा रहा है। कई मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं आप के जरिये सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। शंकराचार्य के बारे में राज्य सभा में काफी कहा जा चुका है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज़ (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग यहां न कहें तो फिर कहां अपने प्रश्नों को उठायें। मैं महसूस करता हूं कि आप परेशानी में हैं। लेकिन हम करें क्या ? मुंगेर का मामला है, मैसूर का मामला है...

MR. DEPUTY SPEAKER : I do not want to shut out anybody. But I would have appreciated if this was mentioned yes-

terday when there was a debate on the Home Ministry's demands.

SHRI J. H PATEL (Shimoga) : This is not a stray incident in Bihar or in U. P. This is a planned thing throughout India. In Mysore State, within the course of six months, it started from Chikmagalur where there was looting, arson and attack on minority communities. Then it happened in Mangalore. Shri George Fernandes went there. Muslims were actually murdered and their properties were damaged. Very recently two weeks back, it happened in Hooghly.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have permitted you. Now please listen. So far as Sankaracharya's speech is concerned, I am told that for tomorrow the Speaker has admitted a Calling Attention Notice. So, it is over now. About other matters, you have brought them to our notice. Whatever both of you have said will be taken note of.

श्री मधु लिमये : आप गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाइये ।

श्री हुकमचंद कछवाय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने नोटिस दिया था आप को । मेरे क्षेत्र उज्जैन के अन्दर केन्द्र द्वारा कंट्रोलर बिठलाया गया है हीरा मिल के अन्दर । उस को बन्द करने का नोटिस लगाया गया है । 4,000 मजदूर बेकार हो रहे हैं । उज्जैन के अन्दर कुम्भ का मेला चल रहा है । इस से वहां अशान्ति बढ़ेगी । मैं कहता हूं कि सरकार उस कंट्रोलर को वहां से हटाये ।

MR. DEPUTY SPEAKER : You should write to the Speaker in a proper way and then bring it to the notice of the House. You should write to the Speaker and he will take note of it.

श्री हुकमचंद कछवाय : मैं ने नोटिस दिया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला । इतने लोगों का सवाल है । 4,000 मजदूर बेकार हो गये हैं । इस से बहुत बड़ी गडबड़ी देश में हो सकती है । उस नगर में इतना बड़ा कुम्भ मेला चल रहा है । इस से अशान्ति बढ़ेगी । मेरी मांग है कि सरकार इस पर चर्चा के लिये समय निकाले । मैं ससद-कार्य मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस के लिये समय दें ताकि हम यहां पर चर्चा कर सकें ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Unless you move the Speaker, I do not think we can do anything

श्री हुकमचंद कछवाय : मैं ने नोटिस दिया है । उस का कोई जवाब नहीं मिला है । आप खुद बतलायें, हम इस मामले को कैसे उठायें और जो लोग बेकार हो रहे हैं उन का क्या होगा ? एक ओर सरकार कहती है कि वह बेकारी दूर करना चाहती है और दूसरी ओर सरकार द्वारा ही लोगों को बेकार किया जा रहा है । ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें?

श्री गंगा रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं पोचम पहाड़ योजना के बारे में कह रहा था कि यह एक वाहिद प्राजैक्ट है तेलंगाना में और इस के साथ हमारी सभी उम्मीदें वाबस्ता हैं । 1962 में इस योजना का श्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था । आठ साल हो चुके हैं । अब तक सिर्फ दस करोड़ रुपया ही इस पर खर्च हुआ है । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर यही रफ्तार रही तो अगले दस साल में भी यह योजना पूरी नहीं होने वाली है । इसमें 66 टी एम सी पानी का एलाटमेंट दिया गया है हालांकि इस की जरूरत 190 टी एम सी पानी की है । इस वक्त सिर्फ 5.7 लाख एकड़ की ही इससे सिंचाई होती है हालांकि 21 लाख एकड़ में सिंचाई हो सकती है ।

जहां तक नार्थ कैनाल का सम्बन्ध है इसका कैंसपशन आज नहीं बल्कि निजाम के जमाने में हुआ था । इस पर सिर्फ पांच करोड़ खर्च होना है और दस हजार एकड़ की सिंचाई हो सकती है । इससे आदिलाबाद को फायदा होने वाला है जहां 36 गांव सबमर्ज होंगे ।

[श्री गंगा रेड्डी]

इसके साथ साथ गोदावरी कैनाल के पानी के इस्तेमाल की भी बात है। इसके इस्तेमाल से जी एन सी पी कडम को लाभ हो सकता है। इसके बिना जी एन सी पी कड़म का कोई फायदा नहीं है। इसके तहत 65,000 एकड़ भूमि में सिंचाई होनी चाहिये। लेकिन चूंकि कड़म नदी में इतना पानी नहीं रहता है कि उतने रकबे की सिंचाई की जा सके, इसलिए इस वक्त 22 हजार एकड़ में सिंचाई हो रही है जबकि नार्थ कैनाल, जी एन सी पी प्राजैक्ट पर आठ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। अगर इसको नहीं किया गया, अगर इसको पानी नहीं दिया गया तो यह जो आठ करोड़ रुपया खर्च किया गया है यह भी वेस्ट जाएगा। लिहाजा मेरी विनती है कि नार्थ कैनाल को भी हाथ में लिया जाए।

जहां तक नार्थ कैनाल का सम्बन्ध है इस वक्त तो वहां 36 गांव सबमर्ज हो रहे हैं लेकिन आगे चल कर 75 हो जायेंगे। ये आदिलाबाद जिले के गांव हैं। इस वक्त आदिलाबाद जिले की ज़मीन में से एक इंच ज़मीन को भी पानी नहीं दिया जा रहा है इस प्राजैक्ट से। मैं चाहता हूं कि आपका जो इखलाकी फर्ज है इसके बारे में उसको आप पहचानें।

जहां तक नागार्जुन सागर का सम्बन्ध है यह भी तेलंगाना एरिया के लिए है। इससे साढ़े 6 लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई होनी थी लेकिन अब उसमें कुछ तबदीली कर दी गई है और अब सिर्फ पांच लाख एकड़ के लिए ही पानी मिल सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी रकबे के लिए भी लिफ्ट इरिगेशन का इंतज़ाम आप करें।

स्वर्णा प्राजैक्ट मेरे जिले में हैं, मेरी कंस्टिट्युएंसी में है। यह एक बहुत ही बदनसीब प्राजैक्ट है। इसको शुरू हुए तकरीबन बारह साल का अर्सा हो चुका है। एक छोटी या मीडियम यह प्राजैक्ट है और इस पर एक करोड़ पचह लाख खर्च होना था। इससे बारह हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। लेकिन इन पिछले बारह सालों में सिर्फ पचास लाख रुपया ही इस पर खर्च हो सका है। लेकिन अब यह समस्या पैदा हुई है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस प्राजैक्ट के बनाने पर कुछ एतराज़ात किए हैं। आप असली हालात को देखें। असली हालात को मद्देनजर रखा जाए तो उनके ये एतराज़ात बिल्कुल बेमानी मालूम आपको देंगे। उनका सिर्फ 450 एकड़ रकबा सबमर्ज होता है। इस 450 एकड़ में से 160 एकड़ रिवर बैड है, 70 एकड़ वैट लैंड है और 220 एकड़ ड्राई और अनकल्टीवेबल लैंड है। मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि इस प्राजैक्ट को पूरा करने के लिए फौरी कदम उठाये जायें और इसको जल्दी खत्म किया जाए। अगर महाराष्ट्र सरकार की बात को मान लिया गया और बांध के साइज़ को छोटा किया गया तो वह एक छोटा सा कुंड बन जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस योजना के साथ आदिलाबाद जिले की खुशहाली वाबस्ता है।

निज़ाम सागर योजना के बारे में दो साल से मैं बराबर कहता आ रहा हूं। यह निजाम के ज़माने की योजना है और इसको अली नवाज़ जंग ने बनाया था। इसकी 25.5 टी एम सी स्टोरेज की कैपेसेटी थी। इससे 2.75 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती थी। अब इसको घटा कर 2 लाख 36 हज़ार कर दिया गया है। इन पिछले तीस सालों में 37 परसेंट उसकी जो कैपेसेटी थी वह कम हो गई है। इसकी वजह यह है कि रेत उस में भरती जा रही है। इस रेत को अगर निकाला नहीं गया तो यह बिल्कुल सिल्टिड हो जाएगी और यह प्राजैक्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अगर

यही रफ्तार सिल्टिग की रही तो यह पक्की बात है कि निज़ाम सागर का वजूद ही नहीं रहेगा।

डा० राव को दावत दी गई थी कि वह आ कर इसको देखें। वहां पर उन्होंने ताज्जुब का इज़हार किया था। वह वहां 25-12-66 को आए थे। उन्होंने कहा था कि 13 टी एम सी की गुंजाइश खत्म हो चुकी है और सिर्फ बारह टी एम सी की गुंजाइश रह गई है। लेकिन इन दो सालों में कुछ नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में फौरी इकदामात किये जायें।

मैं ने कड़म प्राजेक्ट के बारे में कहा है कि नदी में गुंजाइश नहीं है। लिहाज़ा पोचमपहाड़ प्राजेक्ट और नार्थ कैनाल को फौरी तौर पर हाथ में लिया जाए।

रिजनल इम्बैलेंसिस और बैक्वर्ड एरियाज़ की बात भी यहां होती है। तेलंगाना में एजीटेशन चल रहा है। इसकी मेन वजह उस एरिया का बैक्वर्ड होना है। उस एरिया की बैक्वर्डनेस दूर है, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि सतनाला प्राजेक्ट, सुघावाल प्राजेक्ट और दूसरी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्ज़ जो हैं और जिन का सर्वे हो चुका है उनको फौरी तौर पर हाथ में लिया ताकि उस एरिया का डिवेलेपमेंट हो सके।

अलग अलग स्टेट्स में जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुअज़्ज़िज़ मैम्बर आए दिन इसकी चर्चा करते है। पिछले साल जब मैंने उनके भाषणों को सुना तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के जो डिसिशन होते हैं उनके लिए किसी एक मंत्री को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। मैं उन से दरख्वास्त करूंगा कि जब कभी वे कोई बात कहें तो उनकी स्पोर्ट में फैक्ट्स एंड फिगर्ज़ जरूर दें। कृष्णा वाटर डिसप्यूट जो चल रहा है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पानी की तकसीम इस तरह से हुई है कि आंध्र को 800 टी एम सी, महाराष्ट्र को 400 टी एम सी और मैसूर को 600 टी एम सी। डा० राव जब से यहां आए हैं, इस पदवी पर आसीन हुए हैं उन्होंने इसको कैसे तकसीम किया है इसको भी आप देखें। महाराष्ट्र को 182 टी एम सी दिया है, मैसूर को 130 टी एम सी दिया है और आंध्र को सिर्फ चौदह टी एम सी दिया है। आप देखें कि किस के साथ उन्होंने अन्याय किया है? हमारे साथ ही अन्याय किया है। मैसूर और महाराष्ट्र वाले हमेशा उनको ब्लेम करते रहे हैं कि वह पार्शल हैं लेकिन अगर वह पार्शल हैं तो उनकी तरफ हैं, आंध्र की तरफ नहीं हैं। अगर दूसरे प्रदेश वाले आन्दोलन करके कुछ हासिल कर सकते हैं या डरा धमका सकते हैं तो आंध्र वाले भी आन्दोलन करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह रवैया अख्तयार नहीं किया जाना चाहिये।

जब कहीं पर वाटर डिसप्यूट आपस में हल नहीं हो सकता है तो उसको ट्रिब्यूनल को रैफर किया जाता है। इस बारे में आए दिन चर्चा होती है और डा० राव को बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने ला मिनिस्ट्री को सैक्शन चार आफ दी वाटर डिसप्यूट्स एक्ट के तहत रेफर किया है कि ये अलग अलग प्रदेश हैं ये अलग अलग फरीक हैं और अलग अलग ट्रिब्यूनल कायम होने चाहियें। मैं कहूंगा कि बजाय डा० साहब के हाथ मजबूत करने के उनको कमजोर किया जाता है। जिस तरह से इरिगेशन और पावर को हमारे देश में निगलैक्ट किया गया है, जिस तरह से इस के लिए फंड्ज़ कम रखे जाते हैं, उसके लिए लड़ने के बजाय डा० राव को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। मैं चाहता हूं कि उनको जो कम दर्जा कैबिनेट में मिला हुआ है, उसके लिए लड़ा जाता और कहा जाता कि उनको कैबिनेट रैंक

[श्री गंगा रेड्डी]

दे कर इस मंत्रालय के महत्व को बढ़ाया जाए। उनकी पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए हम को कहना चाहिये था। बजाय इसको कहने के उनके इस्तीफे की मांग की जाती है। यह बड़े ही अफसोस की बात है। डा० राव क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट का जब डिसिशन हो तो वह कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि पहली बार हमारे देश में एक काबिल इंजीनियर इरिगेशन और पावर का मिनिस्टर बना है और यह एक गौरव की बात है। उनकी तारीफ की जानी चाहिये। उनको हटाने से समस्या हल नहीं होगी।

मैं यह भी चाहूंगा कि जो नदियां एक से ज्यादा स्टेट्स में से हो कर बहती हैं, उन नदियों पर जो प्राजेक्टस बनाये जायें, जो बंद बनाये जायें, वे कौमी बन्द बनाये जायें।

आप यह भी देखें कि फंड्ज की कमी की वजह से कई प्राजेक्ट्स रुकी पड़ी हैं अधूरी पड़ी हुई हैं। जैसे राजस्थान कैनाल है। हमारे यहां नागार्जुन सागर की योजना है, पोचम पहाड़ की योजना है। इसी तरह से और भी कई दूसरी प्राजेक्ट्स हैं। मैं चाहूंगा कि इनको बड़ी और नेशनल प्राजेक्ट्स माना जाए, इनको कौमी प्राजेक्ट्स मान कर इनको सैंटर अपने हाथ में ले कर जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करे।

यह गांधी शताब्दी का साल है। आपने टारगेट फिक्स किया है कि एक लाख गांवों को आप बिजली देंगे, साढ़े बारह लाख पम्प्स को आप एनरजाइज करेंगे। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस टारगेट को आप अचीव नहीं कर पायेंगे। पावर के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। पावर के बारे में आप बिल्कुल कम्प्लेसेंट हैं। बहुत लापरवाही आप बरत रहे हैं। जो भी टारगेट आप इसके फिक्स करें उनको आप अचीव करें।

आंध्र का जहां तक सम्बन्ध है मैं कहूंगा कि हमारे यहां एवरेज पावर कंजम्शन पर कैपिटा 32 है जबकि आल इंडिया एवरेज 80 है। जो टारगेट आपने रखा है वह जब पूरा हो जाएगा तो हमारे यहां तो 65 होगा जबकि आल इंडिया एवरेज 140 हो जाएगा और मद्रास का 240 हो जाएगा। आंध्र में पावर की बहुत शार्टेज है। वहां सैंट्रली स्पांसर्ड कोई स्कीम नहीं है जैसे राजस्थान में राणा प्रताप सागर है, मद्रास में नैवेली और कलपाकम है, बम्बई में तारापुर है। मैं कहूंगा कि हमें सोमसिला एटमिक पावर प्राजेक्ट दी जाए।

तेलंगाना में कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं। उस कोयले को पावर जैनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं कहूंगा कि फौरी तौर पर कोत्तगुडम और रामगुंडम स्कीम्ज को हाथ में लिया जाए। यहां पर कोल बेस्ड जैनरेशन प्लांट्स स्थापित किये जायें।

मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि जब मिनिस्टर साहब जवाब देना शुरू करें तो मेरे इन प्वाइंट्स का भी जवाब दें।

श्री बंश नारायण सिंह (मिर्जापुर) : सिंचाई और बिजली मंत्री जी ने जो मांगें पेश की हैं वे बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं हैं। बीस बाईस सालों में इन्होंने जो सिंचाई का प्रबन्ध कांग्रेस राज्यों के अन्दर किया है, वह भी बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं है। नहीं के बराबर है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक जितनी सिंचाई की व्यवस्था इस देश में हुई, इस देश में जितनी भूमि में खेती होती है, उस के एक चौथाई भाग में सिंचाई की व्यवस्था हुई है। सिंचाई और बिजली की प्रगति इतनी धीमी चल रही है कि लगता है 50-60 वर्ष इस देश में पूरी सिंचाई व्यवस्था करने में लग जायेंगे। यह बड़ी लज्जा की बात है कि जिस देश में 70-75

फीसदी आदमी खेती का काम करता हो, उस को खाने को न मिले और दूसरे देशों से गल्ला मगाना पड़े। इस लिये मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सारे देश में सिंचाई की व्यवस्था को शीघ्र से शीघ्र करने की कृपा करें।

भारत का किसान आज जिस कठिनाई से गुजर रहा है – यह किसी से छिपा नहीं है। भारत का किसान आज अन्न के बिना मर रहा है, वस्त्र के बिना मर रहा है, पैसे के बिना मर रहा है उस के लड़के मारे-मारे फिर रहे हैं, उन को नौकरी नहीं मिल रही है। उन के लड़के ग्रेजुएट हों, अन्डर-ग्रेजुएट हों, हाई स्कूल पास हों, पचास पचास रुपये की नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं। अगर उन के खेतों को पानी मिल जाय, तो वे वापस अपने खेतों को लौट सकते हैं और इस तरह से सरकार की बेकारी की समस्या 25 फीसदी हल हो सकती है। लेकिन सरकार इस को करने के लिये तैयार नहीं है। किसान की आज जो दुर्दशा हो रही है, वह किसी नेता से छिपी नहीं है, यह सारी जिम्मेदारी उन बड़े बड़े नेताओं पर है, जिनके हाथ में पिछले 20 वर्षों से देश का शासन रहा है। जब तक भारत का किसान सुखी नहीं होगा, तब तक हिन्दुस्तान कभी समृद्धशाली नहीं हो सकता। किसान ही हिन्दुस्तान की एक ऐसी रीढ़ है, जो उस को अन्न दे सकता है, जो आपको सारे सामान दे सकता है, 75 फीसदी आदमी जो खेती करते हैं, उन का बल आपको मिल सकता है वे संगठन कर सकते हैं, देश को समृद्धशाली बना सकते हैं। इस लिये आपको किसानों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

जब तक इस देश में किसानों का आदर नहीं होगा तब तक यह देश ऊंचा नहीं उठ सकता। किसानों की पानी के बिना जो दुर्दशा हो रही है आप देहातों में जाकर देखिये। जिनके खेत पानी के बिना नहीं बोए गये हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्यों कि उनका जीवन केवल खेती पर आधारित है। इसलिये मैं सरकार से अपील करूंगा कि सारी शक्ति लगा कर सब से पहले सिंचाई और बिजली की व्यवस्था करे।

हिन्दुस्तान में जो प्रदेश पिछड़े हुए हैं, भारत सरकार को चाहिये कि काफी रुपया दे कर दूसरे विकसित प्रदेशों के मुकाबले में उन का विकास करे। आप उत्तर प्रदेश को लीजिये–जिस प्रदेश में इतनी नदियां बहती हैं – जहां गंगा बहती है, जमुना बहती है, घाघर और गोमती नदियां बहती हैं—उस प्रदेश की सिंचाई पूरी न हो, वहां के लोग अन्न न पैदा कर सकें, यह कितने शर्म की बात है, यह इस सरकार की कमजोरी है। सरकार को चाहिये था कि इन नदियों का पानी उठा कर सिंचाई की व्यवस्था करती, जिससे कम से कम उत्तर प्रदेश के किसान सुखी हो जाते और अपने खेतों की उपज खुद खाते और दूसरे प्रदेशों को भी देते। आज गंगा और जमुना का पानी बेकार जा रहा है, उस का सदुपयोग नहीं हो रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि—ऐसे प्रदेश हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, इन के विकास की ओर आपका ध्यान तेजी से जाना चाहिये और इन के लिये आपको काफी रुपया खर्च करना चाहिये।

आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की जो दुर्दशा है, वह कही नहीं जा सकती है। मैं अभी बनारस गया था। बनारस की ज्ञानपुर तहसील में चार पैसे का एक बाल्टी पानी मिलता है, लोग वहां पर परेशान हैं, सब के सब कूएं सूख गये है। आप सोचें—जहां पर किसानों की खेती सूख गई हो, अन्न पैदा न हुआ हो, उनके पास कोई बिजनेस न हो, नौकरी न हो, आमदनी का कोई दूसरा जरिया न हो, वहां वे किसान अपने जीवन का निर्वाह कैसे कर सकते हैं। यह सारी जिम्मेदारी

[श्री वंश नारायणसिंह]

सरकार की है और उसे ही इसे देखना चाहिये। जिस वक्त वे बगावत करनी शुरू करेंगे, आन्दोलन करना शुरू करेंगे, तब केन्द्र उनको दबाने के लिये यहां से अपनी फौज भेजेगा। जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, आप उन की मदद लेना नहीं चाहते, जितनी उपेक्षा, लापरवाही, अवहेलना हिन्दुस्तान में किसानों की की गई है, उतनी उपेक्षा दूसरे किसी वर्ग की नहीं की गई है। जब कि सरकार इस बात को जानती है कि किसान हिन्दुस्तान की रीढ़ है, हिन्दुस्तान के लिये गल्ला पैदा करने वाला किसान है, अपने खाने के लिये रख कर बाकी दूसरों को देने वाला किसान है, वह हमेशा शान्त रहने वाला है, वह किसी आन्दोलन या राजनीतिक चक्कर में जानेवाला नहीं है - ऐसे वर्ग की आप मदद नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिये कि आप अपनी पूरी शक्ति से उसको मदद करें।

मिर्जापुर जिले में उपरोक्त एक दक्षिण-पहाड़ी स्थान है, जहां लगभग डेढ़ लाख आदमी बसते हैं। वहां पर किसी के पास पीने के लिये पानी नहीं है, न कूएं हैं, न नहरें हैं और न नदियों का पानी है। वहां के जिलाधीश महोदय ट्रकों के द्वारा वहां पर पानी पहुंचा रहे हैं। ऐसी हालत में वहां खेती कैसे हो सकती है, लोग वहां से छोड़-छोड़ कर बाहर भाग रहे हैं। मैंने वहां अपने एक दौरे में देखा कि एक स्त्री घास की जड़ को काट रही थी। मैंने उससे पूछा—इस जड़ को क्यों खोद रही हो। उसने जवाब दिया—इस जड़ को निकाल कर, धूप में सुखा कर, इसको पीस कर आटा बना कर रोटी बनायेंगे। इस तरह से वहां पर लोग रह रहे हैं। उस जिले के लिये आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहां के लोग कैसे जीवित रह सकते हैं, उन के बाल-बच्चे कैसे जिन्दा रह सकते हैं—सरकार को इस पर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिये।

वहां पर बेलन, सोन, अदवा नदियां हैं, अगर उन को बांध कर उन के बरसाती पानी को रोक दिया जाय तो सारा साल उन को पानी मिल सकता है, उन की खेती भी हो सकती है और पानी को पी भी सकते हैं, जानवरों को भी पिला सकते हैं—लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। 20 वर्ष कांग्रेस राज्य के बीत गये, अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है कि किसानों की तरक्की हो सके। इस की जिम्मेदारी किसानों की नहीं है, इस की जिम्मेदारी इस सरकार की है। जिस क्षेत्र में चार वर्ष सूखे का जमाना बीता हो, उस क्षेत्र के लोगों की आज क्या हालत होगी, आप सहज में इस का अनुमान लगा सकते हैं। उन के घरों में वस्त्र नहीं है, उन के घरों में बर्तन नहीं हैं, सब बर्तनों को बेच-बेच कर खा गये, अपने घर-द्वार को छोड़-छोड़ कर भाग रहे हैं। इस का सारा पाप इस सरकार के सिर पड़ेगा। आज चारों तरफ जो अशान्ति फैली हुई है, इस का मूल कारण यह है कि सरकार की ओर से किसानों की मदद नहीं की जा रही है।

मिर्जापुर का एक हिस्सा कोन-ब्लाक है, उस क्षेत्र में दो हजार वर्षों से गंगा जिस रास्ते से बहती थी, वही रास्ता पिछली बाढ़ से फिर उसने अपनाया है। रास्ता बदलने से 50 बड़े-बड़े गांव गंगा के कटाव में आ गये हैं। उन को बचाने के लिये सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। मैं ने सलाह दी थी कि वहां पर गंगा जी में एक ठोकर बना दी जाय, जिससे गंगा जी की धारा दूसरी तरफ मुड़ जाय और वे गांव बच जायं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। आपको उत्तर प्रदेश की सरकार में हमेशा झगड़ा रहा है कभी संविद की सरकार रही, कभी कांग्रेस की सरकार बनी किन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसी ने कोई काम नहीं किया। यह भ भय की बात है कि केन्द्रीय सरकार अभी तक मत-

खून है, इस में परिवर्तन का अभी कोई खतरा नहीं है, इस लिये आपको चाहिये कि सारे के सारे काम आप अपने हाथ में लें, चाहे प्रदेश का हो या केन्द्र का हो, सब काम अपने हाथ में लेकर करना चाहिये। उन गांवों को बचाने के लिये कम से कम 50 लाख रुपया लगा कर गंगा जी में ठोकर बनवा दीजिये, इस से वे गांव बच जायेंगे और—गंगा जी के पानी को निकाल कर उन किसानों को खेती के लिये दे दीजिये। पहाड़ी इलाकों में कुयें नहीं बन पाते हैं क्योंकि नीचे पत्थर होता है। पत्थर को तोड़ कर नीचे से पानी निकाला जा सकता है लेकिन किसानों के पास इतना रुपया नहीं होता कि वे पत्थर को तोड़कर कुयें से पानी निकाल सकें। यह कार्य तो सरकार ही कर सकती है। सरकार को चाहिए कि पत्थर तोड़कर कम से कम एक कुआं हर गांव में बनवा दे ताकि लोगों की पानी पीने की समस्या हल हो जाये। इस के अलावा सरकार खेती के लिए नदियों को बांध दे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो तीन महीने के भीतर परेशानी में पड़ जायेगी। वहां के आदमी या तो प्यासे मर जायेंगे या फिर वहां से भाग जायेंगे।

सिंचाई मन्त्री से मुझे एक बात और कहनी है कि मिर्जापुर जिले में जाकर आप एक बार देख लें कि वहां के लोग किस तरह से जिन्दा हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते है और कब तक जिन्दा रह सकते हैं बिना खाने पीने के।

सिंचाई मन्त्री से मेरी अन्तिम अपील यह है कि वे जरा अपने इन्जीनियर्स को दुरुस्त करें, उनको चैतन्य बनायें और उन के काम को ठीक करें। जो भी प्लान बनाये जाते हैं उनमें इंजीनियर्स अपने मन की करते हैं। अगर उन से कहा जाय कि यहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, किसान मर रहे हैं, यहां पर ट्यूब-वेल लगा दिया जाये लेकिन वे कभी भी वहां पर ट्यूब वेल लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे ट्यूबवेल वहीं पर लगायेंगे जहां पर कि और भी पंपिंग सेट्स और ट्यूब वेल्स लगे हुए हैं। वे पक्की सड़क के किनारे ही ट्यूब वेल लगायेंगे, इन्टीरियर में ट्यूब वेल लगाने के लिए कभी नहीं जायेंगे। वे लोग गरीब किसानों को कभी देख नहीं सकते हैं। वे नहीं चाहते कि गरीब लोगों को भी पानी पिलाया जाये ताकि उन की जिन्दगी बच सके। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि उन गरीब किसानों को भी आप राहत पहुंचायें।

एक चीज़ और है। जो पुरानी सिंचाई की व्यवस्था थी अब वह बर्बाद हो गई है जब से कांग्रेस का राज्य हुआ। पहले हरएक गांव में बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े बंधे और बड़ी बड़ी झीलें होती थीं। जब बरसात का पानी आता था तो किसान उनको भर लेता था और फिर साल भर उस पानी से खेती करता था, खुद भी पीता था और अपने जानवरों को भी पिलाता था। लेकिन जब से कांग्रेस का राज्य हुआ, वह सारी जमीनें ग्राम समाज को दे दी गई, सारे तालाब, बंधे और झीलें ग्राम समाज को दे दी गई। अब उनकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं हैं। बरसात का पानी उन तालाबों में रुकता नहीं है, सारा पानी बह जाता है जिससे कि सारी खेती सूखी रहती हैं।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने 340 के अन्तर्गत नोटिस दी है। आप मेरे सुझाव को स्वीकार करें। आल इंडिया रेडियो के कर्मचारियों ने आज तनख्वाह नहीं ली है। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। जिन्होंने तनख्वाह लेने से इन्कार किया है वे बड़े कर्मचारी हैं, कलाकार हैं, म्यूजिशियन हैं। उसको आप स्वीकार कर लें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Demands for Grants on Labour and Employment are coming. How is it possible? I know Rule 340. You want this debate to be adjourned. But this matter which

[Mr. Deputy-Speaker]

you want to raise can be raised on the Demands for Grants on Labour and Employment.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उन्होंने आज तनख्वाह नहीं ली है । इसके लिए आप सूचना मन्त्री से कहिये । सरकार ने महगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ जोड़ने का जो फैसला किया था उसको इस मन्त्रालय ने नहीं माना है । वह मन्त्रालय सरकार के उस फैसले को अस्वीकार कर रहा है । यही उन लोगों ने मांग की है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, no, I cannot permit it now. Please resume your seat. But the other Demands are to come. This is not proper. The Demands for Grants on the Ministry of Information and Broadcasting, the Ministry of Labour and Employment, are all coming.

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka) : Sir, I support my friend Shri George Fernandes. This is a very important subject.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am surprised, Mr. Sharma. Please resume your seat.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : जो लोग दिन रात मेहनत करके हमको खबरें सुनाते हैं, म्यूजिक चलाते हैं और आज से तो कामशियल ब्राडकास्टिंग भी शुरू की है, आज सुबह श्री सत्यनारायण सिंह की आवाज भी सुनवाई, उन लोगों ने ही आज तनख्वाह नहीं ली है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are in the labour field for a long time and you are a very effective Member of Parliament; Is it proper at this stage to adjourn the debate ?

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं कब उठा हूं, आप मुझे बताइये ? मैं कहां उठा हूं और कब उठा हूं, आप बताइये ।

एक मन्त्री महोदय यहां पर आये हैं उनसे आप कहिये कि वे सत्यनारायण सिंह से जाकर कहें । उन लोगों ने एक बहुत ही मामूली सी मांग की है ।

MR DEPUTY-SPEAKER : You should contact the Speaker at the proper time. No adjournment is possible now.

श्री मुद्रिका सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत ऐसे कृषि प्रधान देश में विद्युत और सिंचाई विभाग का अपना खास महत्व है । जब इस विभाग को डा० के० एल० राव जैसे दक्ष इन्जीनियर के हाथ में सौंपा गया तो ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच केन्द्रीय सरकार का ध्यान कृषि की ओर गया है । लेकिन जब आये दिन कैबिनेट में बहुत से हेर फेर होते रहे परन्तु न जाने क्यों केन्द्रीय सरकार ने यही उचित समझा कि इतना महत्वपूर्ण विभाग एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में ही रहना चाहिए जोकि इस देश की सिंचाई और विद्युत से सम्बन्धित बातों को कैबिनेट लेवल पर न कह सके, अपनी बात कैबिनेट में दूसरे मिनिस्टर्स को समझा न सके अर्थात एक स्टेट मिनिस्टर के हाथ में ही इस विभाग को रहना चाहिए । जब डा० राव जैसे दक्ष व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो सकते लेकिन उन से कम महत्वपूर्ण विभाग के लोगों को पदोन्नत करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, तो ऐसा मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार का ध्यान कृषि की ओर, जिसका कि सम्बन्ध सिंचाई और विद्युत से है, उतना नहीं है जितना कि जाना चाहिए । यूं तो कहने के लिए हर रिपोर्ट में ऐसी बातें कही जाती हैं कि हम इस देश को, जहां तक खाद्य का सवाल है, आत्म-निर्भर बनाना चाहते हैं, कभी-कभी निश्चित अवधि भी निर्धारित करते हैं लेकिन वह हो नहीं पाता है । उसका कारण यह भी है कि जितना महत्व इस विभाग को देना चाहिए उतना महत्व केन्द्रीय सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है । अनुदानों में भी उतना महत्व नहीं दिया जाता

हैं और एक पावरफुल मिनिस्टर कैबिनेट रैंक का हो जिसके हाथ में यह विभाग रहे, वह भी नहीं किया जा रहा है । मैं तो ऐसा मानता हूं कि यही एक मिनिस्ट्री है जो कि उस विषय को जानने वाले दक्ष व्यक्ति के चार्ज में है लेकिन फिर भी इस देश की आज यह हालत है । मैंने जैसा कहा इस विभाग के प्रति केन्द्रीय सरकार का एक विमाता जैसा व्यवहार है । अगर मैं बिहार राज्य को लूं तो मुझे माफ करेंगे अगर मैं यह कहूं कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य के साथ वही व्यवहार किया है जैसा कि किसी विमाता से हो सकता है ।

मेरे राज्य को देखिये । यह नदियों का राज्य है । यहां पर धरती माता की कोख में अनावृत जल राशि है । जमीन भी यहां की काफी उपजाऊ है और धरती माता के कोख में अनेकानेक रत्न पड़े हैं । फिर भी अभी तक बिहार राज्य सारे हिन्दुस्तान के स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में नीचे से चौथा स्थान रखता था लेकिन अभी जो प्लानिंग कमीशन के सब ग्रुप ने अध्ययन करके रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार हम लोवर से टोप कर रहे हैं । एक ओर तो आप सारे देश के राज्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी ओर इस केन्द्रीय सरकार का यह मेरे साथ व्यवहार है कि हम जहां पर खड़े थे वहां से खिसक कर पीछे जा रहे हैं । क्यों ऐसा हो रहा है ? इसका मूल कारण यह है कि हमारे साथ जो व्यवहार होना चाहिए, उचित व्यवहार नहीं हो रहा है । इसका कारण यह है कि हम भले हैं, हम झगड़ा नहीं कर सकते, हम और राज्यों की तरह से हिन्दुस्तान से अलग होने की बात नहीं करते, और राज्यों की तरह बगावत की बात नहीं करते । हम इस देश की इन्टेगरिटी को कायम रखना चाहते हैं, इसके साथ रहना चाहते हैं । लेकिन अगर यही व्यवहार रहा तो अन्ततोगत्वा बाध्य होकर बिहार राज्य को भी वही करना पड़ेगा जैसा कि और राज्यों से आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई का काम बिहार राज्य में बहुत थोड़ा हुआ है हालांकि बिहार राज्य नदियों का राज्य है । अगर एक सुनियोजित योजना बनाई जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिहार राज्य की एक इंच भूमि भी, कम से कम उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में ऐसी नहीं रहेगी, जहां हम बारहमासी पानी न दे सकें । हम वहां पर चिरस्थायी सिंचाई का प्रबन्ध नहीं कर सके हैं । थोड़ा बहुत अगर किशन है तो कोसी और गंडक में काम चल रहा है । मैं सिंचाई मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दक्षिण बिहार में आपने क्या किया है । सोन हाई लेविल की बात जो चली थी वह भी खटाई में पड़ रही है । बहुत खुशामद और मिन्नत के बाद आपने 70 लाख रुपये दिया है जहां 8 करोड़ का खर्चा है । यह इतनी अच्छी योजना है कि सोन हाई लेविल केनाल को सप्लाई बन सकता है । उसमें ही पानी लेकर हाई लेविल सोन केनाल को फीड करेंगे । उसके लिये भी मैं चिल्ला रहा हूं लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है । अभी तक हमारे के० एल० राव साहब के विभाग वालों ने उसके लिए पैसा नहीं दिया । इतनी महत्वपूर्ण योजना है जिससे कि उस क्षेत्र में काफी सिंचाई हो सकती है । हम अकाल के करार पर खड़े रहते हैं । अकाल में लोगों को जिन्दा रखने के लिए और उनको रोटी कपड़ा देने के लिए आप लाखों और करोड़ों रुपया हर वर्ष खर्च करते हैं लेकिन चिरस्थायी सिंचाई के प्रबन्ध करके लोगों को राहत देने का काम नहीं किया जाता है, उनको भिक्षुक बनने से नहीं बचाया जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है । सरकार की कैसी समझदारी है कि वह इस तरह की नीति को अख्तियार करती है ।

[श्री मुद्रिका सिंह]

बिजली के मामले में आप देखें, उपाध्यक्ष महोदय, तो क्या है ? मेरे राज्य की पोजीशन क्या है। बिहार का कुल क्षेत्र 66,936 वर्ग मील है और उसमें ग्रामीण क्षेत्र 66,147 वर्ग मील है। मद्रास को आप देखें। मद्रास तो हमारे राज्य से बहुत छोटा है, लेकिन स्वराज्य होने के बाद से आज तक बिहार राज्य को जो अनुदान मिला है वह 17 करोड़ रुपये है जबकि मद्रास को 35 करोड 50 लाख है। दूसरे आप यह देखें कि जबकि मद्रास में करीब 14 हजार गांव हैं, बिहार में 67 हजार से ज्यादा गांव हैं। आबादी में कम, गांवों में कम, क्षेत्रफल में कम लेकिन बिहार में अगर आज 40 हजार पम्प चल रहे हैं तो मद्रास में 4 लाख बिजली के पम्प चल रहे हैं। और जो आपको मैंने यह 40 हजार बताए, तो यह भी विगत अकाल की स्थिति में लगे। जबकि लोग भूख से मरने लगे तो उस तरफ ध्यान गया और बड़े जोर शोर से बिजली के पम्प देने की व्यवस्था हुई।

इसके साथ ही साथ यह कहना चाहता हूँ कि ट्रान्समीशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के अभाव में, उनकी कमी की वजह से, जिन गरीब आदमियों ने बिजली के पम्प लगवाए हैं, उन्हे भी पूरा लोड नहीं मिलता और पम्प नहीं चल पा रहे हैं। एक तरफ तो मिनीमम गारन्टी है और दूसरी ओर ये सारी दिक्कते हैं। इस लिए बिहार में जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की मांग है, जितने पम्प लगाये गये हैं उनको समुचित बिजली पहुंचाने के लिए जितनी ट्रान्समीशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइने चाहिए, उसके लिए तत्काल प्रबन्ध होना चाहिए और रुपया मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए मैं एक बार फिर न्याय की भीख मांगना चाहता हूं मिस्टर राव से और केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन से आपके जरिये कहना चाहता हूँ कि जो राज्य पिछड़ा हुआ है बिजली के मामले में, सिंचाई के मामले में, जिसकी प्रति व्यक्ति आय गिरती जा रही है, इसके साथ आप न्याय करें। आबादी के आधार पर न्याय करें, पिछड़ेपन के आधार पर न्याय करें। हमें दूसरे राज्यों के मुकाबले में लान के लिए आपको ज्यादा अनुदान सिंचाई के मामले में भी और बिजली के मामले में भी देना पड़ेगा।

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar): I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1/-."

[Failure to construct Western Kosi Canal (40)].

"That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1/-."

[Failure to Include hydro-electric scheme in the Western Kosi Canal Project. (41)].

"That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1/-."

[Failure to implement Adhwara Project. (42)].

"That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1/-."

[Failure to make Adhwara Project a flood control-cum-irrigation scheme. (43)].

"That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power reduced to Re. 1/-."

[Failure to issue supply orders to manufacture all necessary drilling rigs and boring pumps to Hatia factory for irrigation of entire cultivable land in the country. (44)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1/-."

[Failure to instal floating pumping sets in all the rivers of North Bihar. (45)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1/-."

[Failure to provide adequate funds for completion of Rajasthan Canal. (46)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1/-."

[Failure to remove acute shortage of power and backwardness of North Bihar. (47)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1/-."

[Failure to construct a barrage and dam over Kosi river to carry out a multi-purpose scheme near Barah Kshetra. (48)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1/-."

[Failure to set up warning stations on mountains to forewarn floods in Gandak, Bagmati. Kamla and Kosi rivers. (49)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1/-."

[Failure to conclude an agreement with Nepal Government to complete Western Kosi Canal. (50)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1/-."

[Failure to take over Gandak Project by the Centre. (51)].

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : I beg to move :-

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1/-."

[Failure to introduce effective flood-control schemes. (55)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1/-."

[Failure of the Central Government to take over big irrigation projects of the country. (56)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1/-."

[Policy of giving special assistance to the backward States for irrigation purposes. (57)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced to Re. 1."

[Failure of rural electrification scheme. (58)]

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to imp'ement flood-control scheme effectively. (60)]

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to give timely intimation regarding floods. (61)]

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to check sea and river erosion (62)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Shri Ramavatar Shastri]

[Failure to give proper assistance to the flood affected States. (63)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to check erosion of rivers like Ganga. Punpun, Kosi and Gandak in Bihar. (64)]

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to check erosion in villages of Diara area under Maner, Danapur and other Police Stations in Patna, Bihar (65)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to rehabilitate people affected by erosion. (66)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Inordinate delay in acquiring and allotting land for the rehabilitation of the people affected by erosion. (67)].

"That the demand under the head Multi-purpose River Schemes be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to provide irrigation facilities by taming the rivers (68)]

" That the demand under the head Multi-purpose River Schemes be reduced by Rs.100/-."

[Failure to provide irrigation facilities by taming Ganga river and to generate electricity. (69)].

" That the demand under the head Multi-purpose River Schemes be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to give adequate financial assistance for the completion of Gandak, Kosi, and Sone irrigation projects. (70)].

" That the demand under the head Multi-purpose River Schemes be reduced by Rs. 100."

[Carelessness of the Centres opened to give advance intimation and warning of the floods. (71)]

" That the demand under the head Multi-purpose River Schemes be reduced by Rs. 100."

[Failure to implement Barahia-Mokama Tal irrigation project in Bihar. (72)].

SHRI B. K. MODAK (Hoogly) : I beg to move :--

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Over reliance on foreign collaboration in the matter of implementing Multi-purpose River Schemes. (73)]

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/."

[Failure to increase irrigation potential in consonance with the growing food requirement of the people. (74)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to allot sufficient fund for construction of Mahananda flood protection projects in North Bengal. (75)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to restore and strengthen flood control works damaged by flood of 1968 in Midnapore District and North Bengal. (76)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100 /-"

[Failure to provide adequate provision for irrigation development in the Draft Fourth Plan. (77)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to properly utilise surface and underground water resources in the country. (78)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to take up Dubda Basin Drainage Scheme. (79)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100-/."

[Failure to take up Moyna Basin Drainage. (80)].

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100./-"

[Failure to take up Sunderbans reclamation Schemes as recommended by experts from Holland. (81)]

" That the demand under the head Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to include Tista Barrage Scheme in Fourth Plan. (82)].

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I beg to move :-

"That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to resolve water disputes of the States (92)].

" That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100."

[Un-satisfactory work of Central Water and Power Commission. (93)].

"That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs.100."

[Need to reduced the charges of electrically propelled Tubewells in villages. (94)]

"That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to reduce the electric charges in Bihar. (95)]

" That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100./-"

[Failure to check the unauthorised consumption of electricity. (96)].

" That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100."

[Need to pay the loans asked for by the Bihar Electricity Board. (97)].

" That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-. "

[Need to levy uniform rates of electricity all over the country. (98)],

"That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to arrange regular sittings of the Electricity Consultancy Committee constituted at various levels in Bihar. (99)]

[Shri Ramavatar Shastri]

" That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irirgation and Power be reduced by Rs. 100."

[Failure to stop corruption, nepotism, communalism and favouritism prevalent in Electricity Board of the State (100)].

" That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/--."

[Failure to provide special financial assistance to backward States for the implementation of irrigation Schemes. (101)].

" That the demand under the head Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes be reduced by Rs. 100."

[Failure to pay suitable compensation for the land acquired by the Damodar Valley Corporation. (102)]

" That the demand under the head Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes be reduced by Rs. 100/--."

[Failure in accepting the six-point demands of Damodar Upatyaka Wastuhara Yuva Samiti, Kali Pahari located at Maithan in Dhanbad District. (103)].

" That the demand under the head Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes be reduced by Rs. 100/-."

[Failure in rehabilitation of agriculturists who lost their land as a result of construction of Farakka Dam Project. (104)]

SHRI B. K. MADOK : I beg to move :

" That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to complete Kansabati Project in West Bengal in scheduled time. (105)]

" That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to allot sufficient fund for completion of Kansabati Project during Fourth Plan period. (106)].

" That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs 100 "

[Inadequate supply of floating Pumping sets to utilise river water for Irrigation. (107)].

" That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to supply drilling rigs for boring tubewells. (108)].

" That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to fix uniform and reduced water rates throughout the country. (109)].

" That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Irrigation and Power be reduced by Rs. 100/-"

[Failure to adequately utilise the irrigation potential created. (110)].

MR. DEPUTY-SPEAKER : These cut motions are also before the House.

DR. KARNI SINGH (Bikaner) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, since the time at my disposal is very short, I will right down come to the point. The first point I wish to raise today on the Demands of the Ministry of Irrigation and Power is about speeding up the work on the Rajasthan Canal, apoint which has been raised by many Members of Parliament in this House. The Rajasthan Government, on the one hand, is making a

claim that the Centre is not giving enough funds, and the Centre feels that perhaps adequate funds have been given and the State Government is not using them properly. Now, many of us in this House over the years have been asking the hon. Minister that the Centre should take over the work of the Rajasthan Canal entirely and not leave it to the State and its inefficient administration. We have read in the papers that contractors are blocking the progress of the work of the Rajasthan Canal. Now, when the State of Rajasthan is in the grip of a very severe famine, surely it is a matter of great sorrow that contractors are coming in the way of speedy progress of this mighty canal.

The Indus Water Treaty is coming to an end, and I believe we have only one more payment to make to Pakistan, of Rs. 10 crores. I would very strongly recommend to the Government of India and the hon. Minister that all those funds that we will now be saving should be diverted for the speedy implementation of the Rajasthan Canal project.

The lift channel project, of which the hon. Minister Dr. Rao is the father and founder has now been started, I would only request him that this should get a higher priority.

A little while ago an hon. Member made a reference that Dr. Rao should be raised to the rank of a Cabinet Minister. From the opposition side I whole-heartedly support that and I would like to say that he is a Minister who richly deserves to be raised to Cabinet rank.

The question of rural electrification is causing us a great deal of concern. Only 60,886 villages have been electrified in 18 years and nearly 5 lakh villages still remain to be electrified. Surely, in a country which is ultimately to have an industrial base, adequate electrification of cities and of villages is a matter of higher priority.

The question of floods has been taken up and discussed in this House. In the northern part of Rajasthan, just south of Punjab, we have been regularly having very severe floods, and the hon. Minister knows all about it. Various schemes have been suggested to utilize the flood waters. But I remember having discussed this matter with the hon. Minister, suggesting that instead of diverting these waters into the sand dunes we could utilize these to irrigate the Churu district of Rajasthan which already has a brackish water problem.

I would like to request the hon. Minister to use his influence to see that wherever there is a brackish water problem in any part of this country, it should be studied carefully and the irrigation and other projects be devised in such a way that within a span of say 5 or 10 years brackish water and drinking water problems in the country are solved permanently.

I was in Bombay only a little while ago and I found that this great showpiece city of ours, Bombay, with almost 5 million people, is in the grip of an acute water and electricity shortage. I believe that we are setting up a nuclear power station at Tarapore but the people in Bombay feel that another nuclear power station should be set up much closer to the city so that not only the power problem but also the water problem could be solved by the use of nuclear power for desalinisation purposes. I hope that the hon. Minister would be able to utilise his funds to see that this great city of Bombay is spared from this permanent water and electricity shortage.

This morning a deputation from Rajasthan came and met me. They came from a little town of 15,000 people, of Bidhasar, who have a perennial brackish water problem. They have one or two wells which run dry in the hot weather. This may not be a major problem from an all-India point of view, but they told me that when a deputation waited upon the Chief Minister of the Government of Rajasthan, they were told in an oblique way that this matter was not receiving high priority because the Congress was not returned from this area. Now, I am an independent. I feel that if we want to preserve democracy in our country, it does not make any difference whether it is the Congress Party or the Opposition that runs the State, that it is the duty of

[Dr. Karni Singh]

every welfare government to see that wherever human suffering is present that suffering should be alleviated and that if everything is based on voting, then democracy is degrading itself to a stage where one day, I feel, even democracy in our country may be threatened. I sincerely hope that not only the Chief Minister of Rajasthan in a Congress-run State but even in an Opposition-run States will not compel, coerce or make a voter subservient to threats of blackmail that if they vote for a particular party which is in power at that time, then and then alone will their needs be taken care of.

In many of the towns that are connected by the Bhakra system, large hours of shutdowns take place, quite often on Sundays. I have also brought this matter to the notice of the hon. Minister. In my own home town, Bikaner, where the temperature in the hot weather runs up to 115 degrees, in 115 degrees six to eight hour's shutdowns take place. I am quite sure that the Government is quite capable of diverting electricity from other places to see that if and when such shutdowns take place, adequate electricity is supplied to the people and to the hospitals in particular.

The question of fluctuations on the Bhakra line has also been causing a lot of concern to us. Hospitals are unable to run their x-ray systems because the power is too low. I feel that there should be some arrangements made on the Bhakra system to see that a big rang of power fluctuations do not take place and that expensive equipment belonging to the Government and the people is not destroyed as a result of this.

The Palana colliery question has been before the Government for a long time. The Russian experts who visited Rajasthan have given a scheme for an open cast system on the Palana colliery. I sincerly hope that the Government will give this matter their considered thought and higher priority.

The question of a thermal power station being set up near Palana has been brought to the attention of the hon. Minister and I sincerly hope that this will also be put through soon to augment the supply of electricity in spite of Bhakra.

The Irrigation and Power Ministry is the lifeline of our country. In the years to come, if we want to combat the immense increase in India's population of a crore and thirty lakhs each year, the emphasis on larger use of our waters, which are running waste today, becomes imperative. Ultimately whether civilisation survives will depend on the increased quantum of foodstuffs that we can produce. I, therefore, hope that in the hands of the hon. Minister our fate--in fact, the fate of humanity in India--lies secure and that irrigation projects will receive higher priority than they have done at present.

14.55 hrs.

[SHRIMATI TARKESHWARI SINHA *in the Chair*]

SHRI M. N. NAGHNOOR (Belgaum) : Madam Chairman, I rise to support the Demands of the Irrigation and Power Ministry. At the outset, I warmly congratulate the Irrigation and Power Ministry and the hon. Minister in-charge for developing the irrigation and power potential to the maxium extent in our country.

If we could see from the figures, comparing from 1951 to 1968, during these two decades, we find tremendous progress in our country. The irrigation potential which was 24 million acres in 1951 is of the order of 45 million acres in 1968. The area irrigated in 1 51 was of the order of 24 million acres and now it is 41 million acres. The irrigation from all sources in 1951 was 56 million acres and now it is 86 million acres. In the same way in the power generation also, we have made a remarkable progress. As against 4051 villages which enjoyed the privilege of electricity in 1951, today 60,000 of our rural villages are electrified. Upto the end of the Third Plan, 514,000 pumping sets are having the electric supply. Similarly, we have made a remarkable progress in taking flood control measures by putting up almost about 8000 miles of embankments in our country. So, I

warmly congratulate the hon. Minister who is one of the brilliant engineers of our country.

Coming to the most vexed problem in our country of inter-State dispute over Krishna-Godavari waters, I want to make a few observations. I assure you that I am not obssessed by local patriotism or by any weakness. But I must put it plainly before the House that the whole matter has not been handled in a fair way. The whole trouble seems to be that one of the contending parties of Andhra Pradesh is not wanting to cooperate. The crux of the whole matter is that Andhra Pradesh wants to share more than what it deserves. In regard to the three contending parties of Maharashtra, Mysore and Andhra Pradesh, if we look into the irrigation facilities already provided, Maharashtra enjoys about 6 to 8 per cent, Mysore enjoys about 8 to 10 per cent and Andhra Pradesh enjoys about 26 to 30 per cent of irrigation facilities. In Mysore and Maharashtra, at least an area covering about 20 million people who are inhabiting the dry tracts, is almost touched by famine conditions every alternate year or once in two or three years. Under these circumstances, these two States are pressing for an equitable share of Krishna-Godavari waters.

It is our privilege to settle the dispute between Pakistan and India amicably. The Indus Commission which was appointed in 1941 enunciated broad principles and they could very well come to some conclusion. They had been able to evolve certain principles and work upto an agreed formula to settle the dispute. I may read out a paragraph which says how inter-State disputes could be settled. I am quoting the Commission which made the observation in the year 1941 :

> "The Commission propounded these principles in September, 1941, on the first day of its open session, and after hearing all the interested units, expressed these views in the following terms :-
>
> > "All parties have accepted the general principles which we tentatively formulated on the first day after examining the practice in other parts of the world. It follows from them that the rights of the several units concerned in this dispute must be determined by applying neither the doctrine of sovereignty nor the doctrine of riparian rights, but the rule of equitable apportionment, each unit being entitled to a fair share of the waters of the Indus and its tributaries."

15 hrs.

This is a broad guiding principle. If we had tried to be guided by this principle, we would have been able, very easily, to settle the dispute. In the matter of equitable apportionment of waters, the International Association has also defined certain basis as to how the water should be apportioned, how the water should be shared by the contending parties. They have given five or six clauses. I will not read all of them, but I would mention only two. They are guided by the dry and arid conditions of the area, the contribution, the drainage of that particular basin and the needs of that area. Here in the year 1959-60, Mysore and Andhra Pradesh protested about the *ad hoc* allotment; it was stated by the Mr. Ganga Reddy that Andhra Pradesh should have 800 T. M. cft., Mysore should have 600 T. M. cft. and Maharashtra should have 400 T. M. cft. The Central Government has no *locus standi* to allot any water at all. The basic consideration is that there must be an agreement between the contending parties. As I said earlier, our country is a federal country and all the States are federal units. Over the utilisation of waters and land, each State is a Sovereign body; it is almost a quasi-sovereign body. Under these circumstances, the allocation made by the Government of India was highly improper. In the meanwhile, Andhra Pradesh wants to go ahead with certain projects. We are absolutely not opposed to their going ahead with the projects if that is not going to be prejudicial to our interests. We said, 'Let us decide about sharing of waters.' Meanwhile, it is very unwise and improper on the part of the Government of India to clear away some of the projects and allow Andhra Pradesh to go ahead with some of

[Shri M. N. Naghnoor]

the projects like Nagarjunasagar, appropriating a major share of the water. Once riparian rights are created, then there will be no water left for the other States We have clearly indicated on the floors of the Legislatures of Maharashtra and Mysore and also here that there is dispute over this, there is a little quantity of water, we *bona fide* need more water and, therefore, the issue should be decided. But that is being delayed. I do not attribute any motives to the hon. Minister or the government machinary, but it is a grave act of omission. We are all federal units. Suppose Andhra Pradesh comes and says that they have riparian rights, what will happen ? In spite of our protest, they have gone ahead erecting crest gates of Nagarjunasagar as against the wishes of the contending States. We said that they do not deserve so much of water, but they are trying to appropriate. It is on record that we have protested. A day might come when, if Andhra Pradesh wants to utilise her waters, she will have to take the help of the Army and the Police of Mr. Chavan to allow water from the upper regions. We are all States. Unless there is a broad agreement, we cannot force a particular issue and clear certain projects. I said that, as early as possible, a Tribunal should be appointed. I know, Government is anxious to appoint a Tribunal, but the acts that have already been committed are highly improper and are prejudicial to the interests of the upper regions of Maharashtra and Mysore, and these things have got to be corrected. Even now I would say that the best way to settle this dispute is by agreement because neither the Supreme Court nor the Government of India nor any other authority has any control over these States to make allocations or be guided by their decisions. It is only a Tribunal which can do it. Therefore, I still say that there should be an agreement, failing which there should be a Tribunal. In the matter of this Tribunal, we have heard something new. Now there is a proposal to say that we must have two Tribunals. In the year 1962 or 1963 when Mr. Gulati Commission was appointed, that Commission was appointed to go into the question of Krishna and Godavari waters. Then it was found that Godavari and Krishna basins are so much inter-linked that we cannot think of separate tribunal for Krishna and Godavari. Mr. Gulati made a suggestion that a correct assessment of the resources of the Krishna basin and the Godavari basin must be ascertained and then Mr. Gulati recommended that the surpluses of Godavari basin must be diverted to meet the requirments of Krishna basin. That is being avoided now. The basic reason behind this seems to be that Andhra Pradesh wants to enjoy the maximum share from the Krishna basin and also the Godavari surplus waters to be reserved for them and thus to say 'what is mine is mine and yours is also mine.' The waters of Krishna basin are being taken outside. the Krishna basin to irrigate about 32-35 lakhs of acres of land.

In the Krishna basin Maharashtra and Mysore are suffering and there are famine conditions. When we are unable to grow one single crop, our Andhra friends are anxious to grow two crops per year by making more water available to them. I would most welcome them to grow three crops per year but here we in the upper regions are starving. You can do it. It is most welcome but 20 million farmers are living right from Satara, Bijapur, Belgaum, Dharwar, Gulbarga, Raichur, and Bidar and in those areas people are not able to grow even one crop. They do not have sufficient drinking water facilities. In these circumstances I appeal to the Government that they must be very fair. I want Mr. K. L. Rao to be above all these things. I am sure an eminent engineer of his stature will give his best attention...

AN HON. MEMBER : Above all what ?

SHRI M. N. NAGHNOOR : Above all local considerations, local attachment. I request him to see that it is settled amicably and one must always realise that we are federating units and we have got equal status and the question of riparian rights and sovereignty of States does not solve our problem.

Lastly, Mysore has now in its programme many projects. Upto the end of the Third Plan we have projects costing about

Rs. 321 crores. The total expenditure so far is Rs. 129 crores. So the spill over is still Rs, 191 crores. We have been repeatedly requesting the Government of India to make available some resources for us so that we may implement our projects and they may give early benefits. But the Government of India has been very unkind to us and our projects are being delayed, Therefore, I appeal to the Government of India to find more funds. Secondly our Upper Krishna Project is one of our major projects which is going to irrigate about 20 lakhs acres of land. It is going to irrigate the most arid and famine stricken areas in our Mysore State. Therefore, I request the Government of India to make it a central project and implement it soon.

श्री क०मि० मधुकर (केसरिया) : सरकार की ओर से जो किताबें निकलती हैं उन में इस बात पर ध्यान दिलाया जाता है कि हमारा देश एक ऐसा देश है कि जहां पर घनी आबादी है, उपजाऊ भूमि है और यहां पर खनिज पदार्थ भी काफी मात्रा में पाये जाते हैं। साथ ही साथ यह भी सरकार की ओर से स्वीकार किया जाता है कि हमारे देश के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज बिजली और पानी है। सरकार महात्मा गांधी के उस कथन को भी दोहराती है कि बिना सिंचाई की स्थायी व्यवस्था के खेती एक जुआ है। लेकिन सरकार कौन से प्रयत्न इसके लिए कर रही है इसका कुछ पता नहीं चलता है। पता नहीं वह ऐसा कहते हुए थकती क्यों नहीं है। उसके इस प्रकार के कहने का क्या अर्थ होता है यह मेरी समझ में नहीं आया है। बहुत सी बातें हैं जिनको बार बार दोहराया जाता है। पता नहीं आत्म प्रवंचना के लिए ऐसा किया जाता है या लोगों को ठगने के लिए किया जाता है। जब बातें दोहराई जाती हैं तो क्यों नहीं जो नीति निर्धारित होती है उस पर अमल होता है। जब उन नीतियों पर अमल करने का सवाल आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। आपकी कथनी और करनी में मेल नहीं बैठता है।

हमारे सिंचाई मन्त्री महोदय देश के एक प्रख्यात इंजीनियर हैं। हम बिहार के हैं। इनके यहां होने के बाद भी हमारे बिहार में सिंचाई की क्या व्यवस्था है, बिजली की क्या व्यवस्था है, बाढ़ नियन्त्रण की क्या व्यवस्था है, इन तीनों को आप देखें तो आप को पता चलेगा कि हमारे मन्त्री महोदय जो भले आदमी समझे जाते हैं, मैं भी समझता हूं कि ये भले आदमी हैं, फिर भी उनकी यह भलमनसाहत इस देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक नहीं होती है। समझ में नहीं आता है कि यह क्या बात है। लेकिन उनका भला होना एक बात है और कांग्रेसी राजनीति के कुचक्र में उनका प्रभाव होना दूसरी बात है।

आप देखें कि आज 38 करोड़ एकड़ भूमि में खेती है। बीस बरस के बाद भी बहुत शर्म की बात है कि केवल एक चौथाई से भी कम में सिंचाई की व्यवस्था है। देश में अन्न का अभाव है। ऐसी स्थिति में इतनी कम भूमि में सिंचाई की व्यवस्था का होना बहुत ही शोचनीय बात है। हम अपने देश में पी एल 480 का अनाज मंगाते हैं। यह हमारे देश की प्रतिष्ठा, हमारे देश के गौरव और हमारे देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाली बात है। आज भी हमें पी एल 480 की गुलामी से मुक्ति नहीं मिली है। इससे मुक्ति पाने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। पी एल 480 के तहत अन्न मंगाने के मोह को सरकार छोड़ नहीं पा रही है। सरकार यही कोशिश करती प्रतीत होती है कि हमारी अन्न के मामले में परनिर्भरता बनी रहे।

आप देखें कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में घाटी के जो इलाके हैं, गंगा और दूसरी नदियों के बीच के जो इलाके हैं वहां की जमीन कितनी उपजाऊ है। फिर बिहार में खनिज पदार्थ भी बहुत मिलते हैं। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की या बिहार की

[श्री क० मि० मधुकर]

हालत को आप देखें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में केवल 6 परसेंट में सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है और जहां हो भी पाई है वह भी किसी काम की नहीं है।

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए]

राम गंगा कैनाल बात चल रही थी। वहां पर क्या स्थिति है। वहां पर ठेकेदारों ने लूट मचा रखी है। जो वर्कर वहां काम करते हैं, उनको मजदूरी पाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो वर्कर वहां काम करते हैं, उनके लिए कोई सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इन सबका नतीजा यह है कि जो काम की प्रगति है वह बहुत धीमी है।

तीन योजनायें हम पूरी कर चुके हैं। बिजली की यहां बहुत चर्चा होती है। यह कहा जाता है कि 64,000 गांवों में बिजली दी गई है। लेकिन आप देखें कि देश में गांवों की संख्या कितनी है। साढ़े पांच लाख से अधिक हमारे देश में गांव हैं। समझ में नहीं आता है कि साढ़े पांच लाख गांवों में से केवल 59,000 गांवों को बिजली देना कहां की अचीवमेंट है। कैसे इस पर गर्व किया जा सकता है। यह गौरव की बात नहीं है। आप इस पर दम्भ नहीं भर सकते हैं।

1968--69 के लिए जो लक्ष्य सरकार ने अपने सामने रखा था उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार असफल रही है। यह सरकारी जो आंकड़े हैं उन से स्पष्ट हो जाता है।

सरकार की ओर से एलान किया जाता है कि देश में खेती की तरक्की हो गई है, देश में कृषि क्रान्ति हो गई है। अगर खेती की तरक्की हुई है, कृषि क्रान्ति हुई है, कृषि की पैदावार बढ़ी है तो यह सरकारी व्यवस्था के कारण नहीं बढ़ी है बल्कि इस वास्ते पैदावार बढ़ी है कि मौसम अच्छा रहा है, प्रकृति ने हमारा साथ दिया है। इसका श्रेय आपको नहीं है प्रकृति को है। जब तक सिंचाई की व्यवस्था स्थायी रूप से नहीं होती है, तब तक दम्भ भरने की बात सरकार के लिए आत्म-प्रवन्चना मात्र है।

बिहार में पिछले साल और बंगाल में, आसाम में इससाल बाढ़े आई हैं। बाढ़ों पर नियन्त्रण पाने के लिए आपने कहा है कि हमने ये ये काम किये हैं और बाढ़ों को रोकने में हमें काफी सफलता मिली है। लेकिन आज स्थिति क्या है ? बिहार में कोसी नदी के तटबन्ध टूट जाने से वहां भयंकर बाढ़ आई। असम में भयंकर बाढ़ आई। बाढ़े और सुखाड़ ऐसा लगता है कि हमारी स्थायी समस्यायें बन गई हैं और सरकार इनके आगे कुछ नहीं कर पा रही है। असम में बाढ़ आई। वहां पर बाढ़ों की रोक थाम करने के उपाय केन्द्र अपनाये, यह मांग असम की सरकार करती आ रही है। ब्रह्मपुत्र को नियन्त्रण में लाने के लिए केन्द्र ने एक योजना भी बनाई थी। सरकार ने और मन्त्री महोदय ने यह कबूल भी किया था कि वहां भयंकर बाढ़े आती हैं और उन पर काबू पाना चाहियें। लेकिन आज तक उस योजना को चालू नहीं किया गया है। बाढ़ों पर आज तक नियन्त्रण वहां नहीं पाया जा सका है और न ही वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था हो सकी है, न कोई और ही काम हो सका है। आपके जो एलान होते हैं क्या उनका यही हश्र होगा, क्या आपकी योजनाओं का यही हश्र होगा ? क्या जो घोषणायें आप करते हैं, उनको पूरा करना आपका पावन कर्त्तव्य नहीं है।

जहां तक खेती का सम्बन्ध है, गांवों के किसानों में उसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। लेकिन चूंकि सरकार उनको खेती की सुविधायें देने में, सिंचाई की सुविधायें देने में, बिजली की

सुविधायें प्रदान करने में नितान्त असफल रही है इस वास्ते जिन आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर किसान आगे बढ़े थे, वे अधूरी रह गई हैं। उन में बेचैनी व्याप्त हो गई है। बिहार की स्थिति तो यह है कि आए दिन अखबारों में आता है कि बिजली के कारखाने बन्द हो जाते हैं, बिजली ठप्प हो जाती है जिसके कारण उनके पम्पिंग सैट बन्द हो जाते हैं, बोरिंग पम्प बन्द हो जाते हैं, कारखाने बन्द हो जाते हैं, दूसरे काम ठप्प हो जाते हैं। वहां पर बिजली के ड्रापिंग की जो समस्या है उसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। डी० वी० सी० या दूसरी जगहों से जो बिजली मिलती है उसमें ड्रापिंग की समस्या भी चल रही है। इससे बड़ी परेशानी पैदा होती है किसानों को और दूसरों को। इसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

आप कहते हैं कि किसानों को आप बिजली के कनैकशन देगें। लेकिन आप देखें कि बिजली कनैकशन देने के उनसे बाईस हजार रुपया अग्रिम मांगा जाता है। इतनी राशि वे किस प्रकार से जुटा सकते हैं, इसको आपको देखना चाहिये। फिर आप यह भी देखें कि पांच हार्स पावर से अधिक यदि वे इस्तेमाल करते हैं तो उनको सरचार्ज देना पड़ता है छः रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से। इससे भी उनके सामने एक बड़ी कठिनाई पैदा होती है और अन्न की उपज बढ़ाने के रास्ते में बाधा उपस्थित होती है।

आपने यह भी कहा था कि आप बारह नए पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से किसान से चार्ज करेंगे। यह कहीं कहीं पर तो हो गया है लेकिन कहीं कहीं नहीं हुआ है। इस पर भी आप को गौर करना चाहिये। जो आपने एलान किया था उस पर आपको अमल करना चाहिये। किसानों से बारह पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज होना चाहिए। किसानों के लिए आप को बिजली और सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये। इस मामले में आप संजीदगी से काम नहीं करते हैं। इसकी वजह से किसानों की जो कठिनाइयां हैं, वे बढ़ती हैं।

आप गंडक योजना को लें। मैंने इसके बारे में पिछले साल भी कहा था। गंडक योजना केवल बिहार के लिए नहीं है। इससे यू०पी० को भी लाभ होने वाला है और नेपाल को भी होने वाला है। मैंने इसके बारे में पिछले साल भी कहा था कि केन्द्र इसको अपने हाथ में ले और इसको पूरा करे। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। बिहार में जब संविद की सरकार थी तब उस सरकार के सिंचाई मन्त्री श्री चन्द्र शेखर सिंह ने मांग की थी इसकी, लेकिन उनकी इस मांग की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर आप गंडक योजना को पूरा करना चाहते हैं तो इसको आप अपने हाथ में लें और अगर नहीं लेते हैं तो उतना ही ऋण या अनुदान आप बिहार सरकार को दें ताकि इस योजना को पूरा किया जा सके।

कोसी योजना को आप देखें। पश्चिमी कोसी कैनाल का तीन बार उद्घाटन हो चुका है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि नेपाल से झगड़ा तय नहीं हो पा रहा है इसलिए हम ईस्टर्न कोसी को शुरू नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि नेपाल से आप झगड़े को शीघ्र सुलझायें और ईस्टर्न कोसी योजना को पूरा करें। लार्ड बावेल और श्री नेहरू एक मत थे कि यह मल्टी परपज प्राजैक्ट हो। इससे इरिगेशन भी हो और पावर भी पैदा हो। लेकिन बिजली पैदा नहीं की जा रही है। मैं चाहता हूं कि इसकी ओर भी ध्यान दें। नेपाल सरकार से समझौता होने में अगर कठिनाई होती है और इस योजना को हाथ में नहीं लिया जाता है, इसको खटाई में डाल दिया जाता है तो इससे बहुत हानि होगी।

[श्री कं० मि० मधुकर]

इसी तरह से सोन हाई कैनाल योजना है। पुन योजना है। चदन कैनाल योजना है। इनकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। अभी एक पूर्व वक्ता ने कहा है कि सत्तर करोड़ रुपया रखा गया है। यह बहुत कम राशि है।

मैं चाहता हूं कि पूरे देश के लिए आपका एक इंटीग्रेटिड प्लान होना चाहिये, बिजली के सम्बन्ध में, बाढ़ नियत्रण के सम्बन्ध में, सिचाई के सम्बन्ध में ताकि जो सुविधायें एक जगह पर लोगो को उपलब्ध हैं, वे सुविधायें दूसरी जगह के लोगों को भी उपलब्ध हो सकें। जब आप नेशनल डवेलपमेन्ट की बात करते है तो आप को चाहिए कि जिन कठिनाइयों की तरफ आपका ध्यान दिलाया जाय, उन पर गम्भीरता से विचार करें। मैंने बार बार आपका ध्यान दिलाया है, पत्र भी लिखा है कि मुजफ्फरपुर जिले में मोतीपुर इलाके में बढ़ियारपुर में बाढ़ के कटाव की स्थिति भयंकर होती जा रही है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। 50 लाख रुपया उस पर खर्च हो चुका है इस साल भी खर्च होगा, लेकिन स्थिति यह हो गई है कि अब नेशनल हाइवे नं. 32, रेल्वे लाइन और मोतीपुर शुगर फैक्टरी—इन सब पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। बाद में आप कहियेगा कि कुछ नहीं हो सका। समय रहते आप ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला है।

बिजली के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि बिजली की दर कम करना तो दूर, उस को बढ़ाने की बात की जा रही है। कोसी से अगर हम बिजली पैदा करें तो बहुत सस्ते दर पर वहां बिजली पैदा हो सकती है—लेकिन उस तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरह से राजस्थान कैनाल के मामले मे कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। यह सही है कि आपकी सरकार से वहां के मुख्य मन्त्री सुखाड़िया जी ने मांग की है कि राजस्थान कैनाल को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले, लेकिन पता नहीं, आप उसको क्यों अपने हाथ में नहीं लेते हैं। साढ़े तीन लाख लोग वहां पर विस्थापित हो चुके हैं। राजस्थान जैसे इलाके में, जो मरुभूमि है, अगर सरकार की लापरवाही इसी तरह से चलती रही तो सूखा ही नहीं, वहां भयंकर अकाल भी पडनेवाला है।

यही स्थिति फरक्का प्रोजेक्ट है—उस इलाके में भी बहुत से लोग विस्थापित हो चुके हैं, उनको सैटिल करने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। पाकिस्तान के साथ जो आपकी बातचीत चल रही है, वह भी अभी तक हल नहीं हो पाई है।

आप अपने एन. पी. सी. सी. की ओर देखिये उसका वर्कशाप आगरा में है। आगरा में वर्कशाप होते हुए भी आपने बहुत सी प्राइवेट कम्पनियों के साथ डायरैक्ट कांट्रेक्ट किये हुए हैं। जिसका नतीजा यह होता है कि उसमें पूरा उत्पादन नहीं होता है, उसकी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि एन. पी. सी. सी. के वर्कशाप का पूरा इस्तेमाल होना चाहिये और प्राइवेट लोगों को जो कांट्रेक्ट दिये जाते हैं, वे बन्द होने चाहिये।

बागमती योजना के सवाल को लीजिये। उस जिले में आपने फ्लड कंट्रोल की योजना बनाई है जो वहां के किसानों के लिये भयंकर आघात सिद्ध हो रही है। क्योंकि बागमती नदी में जो कीचड़ आता है, उस कीचड़ से किसानों के जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है लेकिन आप की योजना से जमीन बन्जर हो जायेगी। क्योंकि उस कीचड़ का इस्तेमाल जमीनों में नहीं हो पायेगा। इसलिये आप से अनुरोध है कि आप ऐसी योजना बनायें जिससे फ्लड कन्ट्रोल के साथ साथ सिचाई हो सके,

उस कीचड़ का इस्तेमाल हो सके। कोसी, बागमती, गण्डक योजनाओं के लागू होने का मतलब होता है कि बिहार की 60 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी और यदि हम केवल एक टन फी एकड़ ले लें तो बिहार से आपको 60 लाख टन अनाज मिल सकता है। जो देश की खपत की बहुत हद तक पूर्ति कर सकता है।

अगर आप इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे तो चाहे आप कितने ही बड़े आदमी हों, लेकिन प्रशासन के मामले में, योजनाओं के मामले में आपकी क्षमता और योग्यता का इस्तेमाल नहीं हो पायेगा और देश समझेगा कि इतना बड़ा कौम्पीटेन्ट इन्जीनियर मिनिस्टर होने के बाद भी कोई काम नहीं कर सका। इसलिये मैं चाहूँगा कि जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, उनके बारे में आप कैटेगोरिकल आन्सर दीजिये—ब्रह्मपुत्र, गण्डक, कोसी योजना, कटाव के विषय में, राजस्थान कैनाल के विषय में—बिहार की सिंचाई योजनाओं के बारे में अपने भाषण में प्रकाश डालें।

श्री अहमद आगा (बारामूला) : सभापति जी, मुल्क की तरक्की का इनहसार बिजली और पानी पर है। कांग्रेस सरकार ने पिछली पांचसाला योजनाओं और पिछले दो सालों की योजनाओं से मुल्क की काफी तरक्की की है। इन्होंने 81 मिलियन एकड़ जमीन को सैराब करने की योजना बनाई थी, जिसमें से 35 मिलियन एकड़ जमीन सैराब हो चुकी है। 13 मिलियन एकड़ जमीन सैलाब की तबाही से बचाई। बिजली 1951 के मुकाबले चार गुना ज्यादा जेनरेट हुई, एटामिक पावर स्टेशन बम्बई, मद्रास और राजस्थान में बनाये। इस तरह से मुल्क की काफी तरक्की हुई है।

मैं काश्मीर को रिप्रेजेन्ट करता हूँ। मैंने यह देखा है कि काश्मीर में भी काफी तरक्की हुई है। जहां तक सड़कों का ताल्लुक है-सड़कों को जाल बिछाया गया है। मगर जहां तक बिजली और सिंचाई का ताल्लुक है—मैंने काश्मीर में देखा है—पिछले 20 सालों में बहुत कम तवज्जह दी गई है। वहां कोई मेजर या मीडियम प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिये गये, बिजली को कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया गया। रियासत के गवर्नर ने अभी कुछ देर पहले अपने एड्रेस में कहा था—रावी और तवी कम्पलेक्स को हाथ में लिया जाय। लेकिन मैंने इस बजट में ऐसी कोई चीज नहीं देखी जिससे जाहिर होता है कि इन पर काम शुरू हो सकेगा। लेकिन चूंकि यह बात गवर्नर के एड्रेस में कही गई है इसलिये शायद सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट चौथी पांचसाला योजना में इस को ले सकेगी। जम्मू का वह सारा इलाका जो जम्मू और कठवा के दरम्यान पड़ता है पानी की बून्द-बून्द के लिये तरस रहा है, उन को पीने का पानी मोयस्सर नहीं है। अगर वहां पर हमारा रावी और तवी ब्लाक बन जाय, जो कि बहुत देर से शुरू हुआ है, तो उम्मीद करनी चाहिये कि वहां की एक लाख बीस हजार एकड़ जमीन सैराब हो सकेगी। हालांकि जम्मू का बहुत ज्यादा इलाका ऐसा है, जो सैराब नहीं होता है, और वह शायद फिर भी ऐसा ही रहे। काश्मीर की बेश्तर जमीन जो जेरे-काश्त है, वह ज्यादातर कुओं से सेराब होती है, वाटर-सप्लाई के लिये पिछले साल हमको 90 लाख रुपये मिले थे, इस साल उस को घटाकर 80 लाख कर दिया गया है। पिछले साल बिजली के लिये हम को 514 लाख रुपये मिले थे, इस साल मैंने देखा है कि उसमें भी कमी कर दी गई है, इस साल 511 लाख रुपये दिये जाने वाले हैं। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि काश्मीर में इस सिलसिले में कुछ कम तवज्जह दी जा रही है। मैं देखता हूं कि दूसरी रियासतों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काफी रुपया खर्च किया जा रहा है, वहां पर काफी काम हुआ है मुल्क ने काफी तरक्की की है, लेकिन काश्मीर को फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क के एक बाजू को कमजोर नहीं

[श्री अहमद आगा]

रखा जा सकता, अगर बाजू की एक अंगुली भी कमजोर रहेगी तो सारा बाजू दुखेगा। कहा गया है—

समुन्द्र से मिले प्यासे को शबनम,
बखीली है, यह रजाकी नहीं है।

मैं देखता हूं कि काश्मीर के लिये जो रुपया इस सिलसिले में दिया जाता है, वह बहुत कम है और वहां की सरकार उस से कुछ नहीं कर पाती। हमारे पास 1947 से पहले बिजली का जो प्रोजेक्ट था, वही अब भी है, पिछले 22 सालों में कुछ नहीं हुआ। वहां चार प्रोजेक्ट्स बन सकते थे, हाथ में लिये भी गये थे—अपर सिन्धु, लोअर जेहलम, चिनैनी, सलाल। चिनैनी में कुछ काम हुआ है। लोअर जेहलम, मेरी कांस्टीचुएन्सी में पड़ता है, जब उसको देखता हूं तो ऐसा नजर आता है कि काम बन्द हो गया है। बड़ी सुस्त रफ्तार से वहां पर काम हो रहा है। अपर-सिन्ध की भी यही हालत है। सलाल के लिये यह वायदा था कि उस को सेन्ट्रल प्रोजेक्ट के तौर पर लिया जायेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहां पर पुल बनाना जरूरी था, जो इण्डस्ट्रीयल एरिया को उस के साथ मिला सके, वह पुल बन चुका है—उस का 3200 फुट का स्पान है, लेकिन बिजली पैदा करने के सिलसिले में अभी तक कोई मौजू कदम नहीं उठाये गये।

हमारे काश्मीर में एक ही सीजन चलता है। लोग तीन-चार महीने काम करते हैं बाकी साल भर बेकार बैठे रहते हैं। वहां पर बहुत से कारखानों की जरूरत है। वहां पर बहुत सा काम प्रोवाइड किया जा सकता है लेकिन जब तक बिजली नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। वहां पर 8 हजार मुरब्बा मील पर जंगल वाकय है जहां से तजार्ती लकड़ी बरामद हो रही है। वहां पर फूड बुड इन्डस्ट्रीज का बहुत स्कोप है लेकिन उसके लिए बिजली की जरूरत है।

यहां पर कश्मीर के मुताल्लिक जब भी बात होती है तो वह एक्तिसादी मसले को लेकर बहुत कम होती है, सियासी मसले पर ही ज्यादा तर होती है। अगर सियासी मसले की जगह पर एक्तिसादी मसले को ही उठाया जाये और वहां पर तरक्की के रास्ते पैदा किये जायं, लोगों को रोजगार मिले तो फिर वहां पर कोई समस्या ही नहीं है। कोई समस्या रह नहीं सकती है। आज वहां पर सारे के सारे लोग बेकार हैं, वे क्या करेंगे? हमारे यहां दस हजार मिलियन टन बाक्साइट का सर्वे हो चुका है लेकिन उसके मुताल्लिक अभी तक कुछ नहीं किया गया है। लाइम-स्टोन 85 हजार मिलियन टन है, सलाल में 10 हजार मिलियन टन के करीब मौजूद है। जिप्सम 76 हजार मिलियन टन है, ग्रैफाइट 48 हजार मिलियन टन है लेकिन उसके लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय यहां पर यह एश्योरेंस देंगे कि इस फाइव ईयु प्लान में बिजली और सिंचाई का काम वहां पर हाथ में लिया जायेगा और उसको मुकम्मिल करने की कोशिश की जायेगी। रियासती सरकार तो इसलिए वहां पर ज्यादा काम नहीं कर पाती है क्योंकि उसको बहुत कम पैसा मिलता है। वह तो सिर्फ मेन्टीनेन्स का काम ही करती है। मुझे उम्मीद है कि मन्त्री जी अपनी तकरीर में यह एश्योरैन्स देंगे कि वहां पर लोवर जेलम और सलाल में तेज रफ्तार से काम किया जायेगा और रावी व तवी कम्पलेक्स पर खासी तेजी से काम किया जायेगा।

ہوتا ہو کہ ان پر کام شروع ہو سکے گا۔ لیکن چونکہ یہ بات گورنر کے ایڈریس میں کہی گئی ہے اس لئے شائد سنٹرل گورنمینٹ چوتھی پانچ سالہ یوجنا میں اس کو لے سکے گی۔جموں کا وہ سارا علاقہ جو جموں اور کھٹوعا کے درمیان پڑتا ہے پانی کی بولد بولد کے لئے ترس رہا ہے۔ان کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ اگر وہاں پرھمارا راوی اور توی بلاک بن جائے جو کہ بہت دیر سے شروع ہوا ہے تو امید کرنی چاہئے کہ وہاں ایک لاکھ بیس ہزار ایکڑ زمین سیرآب ہو سکے گی۔حالانکہ جموں کا بہت زیادہ علاقہ ایسا ہے جو سیرآب نہیں ہوتا ہے۔اور وہ شائد پھر بھی ایسا ہی رہے۔کشمیر کی بیشتر زمین جو زیر کاشت ہے وہ زیادہ تر کوؤں سے سیرآب ہوتی ہے۔ واٹر سپلائی کے لئے پچھلے سال ہم کو ۹۰ لاکھ روپئے ملے تھے اس سال اس کو گھٹاکر ۸۰ لاکھ کر دیا گیا ہے۔پچھلے سال بجلی کے لئے ہم کو ۵۱۴ لاکھ روپئے ملے تھے۔اس سال میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔اس سال ۵۱۱ لاکھ روپئے دئے جانے والے ہیں۔میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ کشمیر میں اس سلسلے میں کچھ کم توجہ دی جارہی ہے۔میں دیکھتا ہوں کہ دوسری ریاستوں میں بڑے بڑے پراجیکٹس پر کافی روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔وہاں پر کافی کام ہوا ہے۔ملک نے کافی ترقی کی ہے لیکن کشمیر کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ملک کے ایک بازو کو کمزور نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر بازو کی ایک

اسکے علاوہ اس وقت میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔

[شری احمد آغا (بارامولا)-سبھاپتی جی-ملک کی ترقی کا انحصار بجلی اور پانی پر ہے۔ کانگریس سرکار نے پچھلی پانچسالہ یوجناؤں اور پچھلے دو سالوں کی یوجناؤں سے ملک کی کافی ترقی کی ہے۔انھوں نے ۸۱ ملین ایکڑ زمین کو سیرآب کرنے کی یوجنا بنائی تھی۔ جس میں سے ۳۵ ملین ایکڑ زمین سیرآب ہو چکی ہے۔۱۳ ملین ایکڑ زمین سیلاب کی تباہی سے بچائی۔ بجلی ۱۹۵۱ کے مقابلے چار گنا زیادہ جینریٹ ہوئی۔ ایٹا مک پاورسٹیشن بمبئی، مدراس اور راجستھان میں بنائے۔اس طرح سے ملک کی کافی ترقی ہوئی ہے۔

میں کشمیر کو ریپریزنٹ کرتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کشمیر میں بھی کافی ترقی ہوئی ہے۔جہاں تک سڑکوں کا تعلق ہے۔ سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے - مگر جہاں تک بجلی اور سنچائی کا تعلق ہے۔ میں نے کشمیر میں دیکھا ہے۔پچھلے ۲۰ سالوں میں بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ وہاں کوئی میجر یا میڈیم پروجیکٹ ہاتھ میں نہیں لئے گئے۔بجلی کا کوئی بڑا پروجیکٹ ہاتھ میں نہیں لیا گیا۔ریاست کے گورنر نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے ایڈریس میں کہا تھا۔ راوی اور توی ہیلیکس کو ہاتھ میں لیا جائے۔لیکن میں نے اس بجٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے ظاہر

[شری احمد آغا]

انگلی بھی کمزور رہے گی تو سارا بازو دکھے گا- کہا گیا ہے کہ

سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم
بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے-

میں دیکھتا ہوں کہ کشمیر کے لئے جو روپیہ اس سلسلے میں دیا جاتا ہے وہ بہت کم ہے اور وہاں کی سرکار اس سے کچھ نہیں کر پاتی-ہمارے پاس ۱۹۴۷ سے پہلے بجلی کا جو پراجیکٹ تھا وہی اب بھی ہے-پچھلے ۲۲ سالوں میں کچھ نہیں ہوا ہے-وہاں چار پراجیکٹس بن سکتے تھے-ہاتھ میں لئے بھی گئے تھے- اپرسندھ-لوئر جہلم-چھنیدی اور سلال- چھنیدی میں کچھ کام ہوا ہے- لوئر جہلم میری کانسٹیچوینسی میں پڑتا ہے-جب اس کو دیکھتا ہوں تو ایسا نظر آتا ہے کہ کام بند ہو گیا ہے-بڑی سست رفتار سے وہاں پر کام ہو رہا ہے-اپرسندھ کی بھی یہی حالت ہے-سلال کے لئے یہ وائدہ تھا کہ اس کو سنٹرل پراجیکٹ کے طور پر لیا جائیگا-لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا-وہاں پر پل بنانا ضروری تھا-جوانٹرسٹرل ایریا کو اس کے ساتھ ملا سکے-وہ پل بن چکا ہے-اس کا ۳۲۰۰ فٹ کا سپان ہے لیکن بجلی پیدا کرنے کے سلسلے میں ابھی تک کوئی موزوں قدم نہیں اٹھائے گئے-

ہمارے کشمیر میں ایک ہی سیزن چلتا ہے-لوگ تین چار مہینے کام کر لیے ہیں باقی سال بھر بیکار بیٹھے رہتے ہیں-وہاں پر بہت سے کارخانوں کی ضرورت ہے-وہاں پر بہت سا کام پروائیڈ کیا جاسکتا ہے لیکن جب تک بجلی نہیں ہوگی تب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے-وہاں پر ۸ ہزار مربع میل پر جنگل واقع ہے جہاں سے تجارتی لکڑی برآمد ہو رہی ہے-وہاں پر ووڈ انڈسٹریز کا بہت اسکوپ ہے لیکن اس کے لئے بجلی کی ضرورت ہے-

یہاں پر کشمیر کے متعلق جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ اقتصادی مسلہ کو لیکر بہت کم ہوتی ہے-سیاسی مسلہ پر ہی زیادہ تر ہوتی ہے-اگر سیاسی مسلہ کی جگہ پر اقتصادی مسلہ کو ہی اٹھایا جائے اور وہاں پر ترقی کے راستے پیدا کئے جائیں-لوگوں کو روزگار ملے تو پھر وہاں پر کوئی سمسیا ہی نہیں ہے-کوئی سمسیا رہ نہیں سکتی ہے-آج وہاں پر سارے کے سارے لوگ بیکار ہیں وے کیا کرینگے-ہمارے یہاں دس ہزار ملین ٹن باکسایٹ کا سروے ہوچکا ہے لیکن اس کے متعلق ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا ہے-لائم اسٹون ۸۵ ہزار ملین ٹن ہے-سلال میں ۱۰ ہزار ملین ٹن کے قریب موجود ہے-جپسم ۷۶ ہزار ملین ٹن ہے-گریفائیٹ ۴۸ ہزار ملین ٹن ہے لیکن اس کے لئے کوئی بھی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے جارہے ہیں-

مجھے امید ہے کہ منتری مہودے یہاں پر یہ اشیورینس دینگے کہ اس فائیو ایر پلین میں بجلی اور سنچائی کا کام وہاں پر ہاتھ میں لیا جائیگا اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائیگی-

ریاستی سرکار تو اس لئے وہاں پر زیادہ کام نہیں کر پاتی ہے کیونکہ اس کو بہت کم پیسہ ملتا ہے۔ وہ تو صرف مینٹی۔ نینس کا کام ہی کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ منتری جی اپنی گرانٹ میں یہ اشیورینس دینگے کہ وہاں پر لوور جیلم اور سلال میں تیز رفتار سے کام کیا جائیگا اور راوی و توی کمپلیکس پر خاص تیزی سے کام کیا جائیگا۔ اس کے علاوہ اس وقت میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔]

श्री राम चरण (खुर्जा) : चेयरमैन साहब, हमारे देश की ५० फीसदी आबादी किसानों के साथ बंधी हुई है। किसानों की जिन्दगी इस देश में पानी के साथ बंधी हुई है। और पानी की क्या स्थिति है? हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं, आजादी के बाद से अभी तक उनका एक चौथाई हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं हो पाया है। वैसे तो माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे मिनिस्टर बड़े एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन अभी तक कितने परसेन्ट पानी का उपयोग किया जा सका है, इस बात को भी तो आप देखें। कितना पानी अभी तक किसानों को दिया गया है? तीन पंचवर्षीय योजनाओं में करीब करीब 534 मेजर और माइनर प्रोजेक्ट्स चलाये गये लेकिन उनमें से अभी तक करीब पचास परसेन्ट ही पूरे हुए हैं। साथ ही आप इस बात को भी देखें कि किसानों को जो बिजली मिलती है वह किस रेट पर मिलती है? इंडस्ट्रीज के लिए पूंजीपतियों को तो सस्ती दर पर बिजली दी जाती है लेकिन किसानों को वही बिजली मंहगी मिलती है। मैं कांग्रेस सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर वह इस देश की भलाई चाहती है और किसानों के हित की बात सोचती है तो वह किसानों को सस्ते दामों पर बिजली और पानी दे। पानी उपलब्ध करने के जो साधन है उनमें मेजर प्रोजेक्टस हैं, माइनर प्रोजेक्टस हैं। इसके अतिरिक्त आप नहरों के जरिए से, ट्यूबवेल्स के जरिए से और लिफ्ट इरीगेशन के जरिए से किसानों को पानी दे सकते हैं। जहां तक मेजर प्रोजेक्ट्स का सम्बन्ध है, वे अधिकतर पूरे नहीं हो पाये हैं। जहां जहां पर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे बिहार में या यू० पी० के पूर्वी जिलों में तो वहां पर आप लिफ्ट इरीगेशन की थोड़ी बहुत सुविधाएं प्रदान करते हैं लेकिन वह चीज सीजनल होती है, थोड़े समय के लिए ही होती है, उससे उनकी पानी की समस्या हल नहीं होती है। इस बजट में यू० पी० के लिए आपने इस तरह का कोई प्रयोजन नहीं किया है कि वहां पर किसानों को सस्ती दरों पर और समय पर पानी मिल जाये।

वैसे तो हमारे मिनिस्टर साहब बड़े एक्सपर्ट हैं, अन्तर्राज्यीय वाटर रिसोर्सेज को झगड़ों को निपटाने के लिए इन्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ऐक्ट बनाया गया है, लेकिन उससे अभी तक कोई लाभ प्रतीत नहीं हुआ है। आज तक जितने भी मसले उठे हैं उनका कोई निपटारा उस एक्ट के जरिए से नहीं हो पाया है। आप कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा के झगड़े को देखें, वे आज तक नहीं तय हो पाये हैं। बड़े अफसोस की बात है। आखिर वजह क्या है? इस कमीशन में जो काम करते हैं, जो आफिसर्स हैं वे स्टेट्स को बगलाते हैं और कोई हल निकलने ही नहीं देते हैं। आपने गुलाटी कमीशन बनाया, पहले उसका टर्म कितने दिन का था और फिर बाद में आप ने उसको कितने एक्सटेंशन दिए? इससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारी गण अपने स्वार्थ के लिए स्टेट्स को लड़ाते रहते हैं न कि उनके डिप्यूट्स को सेटिल करते हैं। आपने मिनिस्ट्री आफ इरीगेशन एंड पावर के अन्तर्गत बहुत से बोर्ड और कमीशन्स बनाये हैं लेकिन मेरे खयाल से

[श्री राम चरण]

उनकी सिफारिशों पर कोई अमल, इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है।

मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि अगर किसानों को समय पर पानी नहीं दिया गया, और उन को इरीगेशन फेसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई तो फिर कहीं ऐसा न हो कि किसानों का रुख भी कम्युनिस्टों की तरफ हो जाये । अभी तक तो इस देश में जो कम्युनिस्ट हैं वे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं, बल्कि लेबर क्लास वाले ही हैं लेकिन अगर किसानों के डिमाग में भी यह बात पैदा हो गई कि यह सरकार किसी प्रकार से भी उनको सुविधा देने में समर्थ नहीं है तो हो सकता है कि वे भी कम्युनिस्टों के साथ बैठकर कम्युनिस्ट हो जाय। इसलिए आपका ध्यान इस ओर अवश्य जाना चाहिए।

एक बात और है। फरक्का प्रोजेक्ट का ओरिजनल एस्टीमेट 70 करोड़ का था लेकिन उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट 160 करोड़ का हो गया । इसकी वजह क्या है ? इसकी वजह है नौकरशाही की लापरवाही। इनीशल स्टेज पर कम कास्ट दिखाकर वे लोग प्रोजेक्ट्स को पास करा लेते हैं और फिर बाद में उनकी कास्ट बढ़ जाती है। जब उसका ओरिजनल एस्टीमेट 70 करोड़ का था और बाद में वह 160 करोड़ का हो गया तो उसका मतलब है कि उसमें लूपहोल है। फरक्का प्रोजेक्ट से इस देश को लाभ होगा लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री आफ पावर ऐन्ड इरीगेशन ने उसको ओरिजनल कास्ट पर बनाकर क्यों नहीं तैयार किया ? उसकी क्या वजह है ? उसका कारण है अधिकारियों की लापरवाही। इस मिनिस्ट्री में दो विंग है, एक तो वाटर विंग है दूसरा पावर विंग है। दोनों विंगज में एक हजार इंजीनियर्स हैं । वे एयर कन्डीशन्ड बिल्डिंग्ज में बैठकर हिन्दुस्तान का जो नक्शा तैयार करते हैं वह गलत होता है। लिहाजा मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस बात को नोट कर लें कि इस मिनिस्ट्री के दोनों पावर और वाटर विंग्ज की वर्किंग को एनालाइज किया जाये और देखा जाये कि कितना वर्क है, सीजनल वर्क है या फुल टाइम वर्क है। उनको फुल टाइम वर्क प्रोवाइड किया जाये तथा उनकी पूरी यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाये।

इसके अलावा सिड्यूल्ड कास्ट की एक बात और मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं सिड्यूल्ड कास्ट से ताल्लुक रखता हूं। लिफ्ट वाटर इरीगेशन बोर्ड में जो नान-मिनिस्ट्रियल स्टाफ और जो टेक्निकल स्टाफ है, उसमें क्लास 3 और गजेटेड पोस्ट्स के अन्दर, सिड्यूल्ड कास्ट की किसी भी केटेगरी को आप लें, सिड्यूल्ड कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ है। इसकी क्या वजह है । वहां के आफीसर्स सिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को गले नहीं लगाना चाहते। मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आन्ध्र की मिसाल को याद रखें। आन्ध्र के अन्दर जो जुल्म होता है तो क्या यहां पर उस जुल्म को बर्दाश्त करेंगें ? क्यों नहीं सिड्यूल्ड कास्ट की क्लास 3, क्लास 4 और गजेटेड पोस्टों में उनका कोटा पूरा करने की कोशिश की जाती है। जहां तक डिपार्टमेंटल प्रोमोशन्स और टेक्निकल पोस्टों की बात है, सिड्यूल्ड कास्ट के क्लास 3 का प्रोमोशन का कोटा आप उठाकर देखेंगें तो निल के बराबर मिलेगा। इसकी वजह क्या हैं ? यहां के ब्यूरियोक्रेटिक आफीसर्स हैं जोकि तासुबी हैं। वे यह नहीं चाहते कि इस देश का निर्माण हो, वे नहीं चाहते कि सामाजिक उन्नति हो । तो मैं मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि जहां तक देश के किसानों का सवाल है, उनको आप पानी दीजिए।

मैं बाढ़ की बात कहता हूं। इन्होंने सन् 1954 में फ्लड कन्ट्रोल एक्ट पास किया।

उसके अन्तर्गत हर स्टेट के अन्दर फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड सेट अप किये गये ताकि ये फ्लड को कन्ट्रोल करें । इन्होंने फ्लड कन्ट्रोल किया । लेकिन अगर वास्तव में ये देखेंगें तो जितने इन्होंने फीगर्स दिये हैं कि इतने विलेजेज को प्रोटेक्ट किया गया, तो क्या मिनिस्टर साहब बता सकते है कि जिस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया, उसमें क्या फिर बाढ़ नहीं आई । बाढ़ आई है । डिफेक्ट यह है कि यहां के जो दरिया हैं यहां के जो रीवर्स हैं, इनके बेड्स में जो सिल्ट आती है उसको जब तक यह नहीं रोकेंगें, तब तक इस देश के फ्लड्स को नहीं रोक सकते हैं । इसके लिए अगर आप उसके ऊपर केचमेंट एरियाज के अन्दर सिल्ट को प्रिवेन्ट करने के लिए स्टेप लेंगें तो आप फ्लड्स को रोक सकते हैं । जहां तक फ्लड्स की बात है, मिनिस्टर साहब टेक्निकल आदमी हैं, वे जानते होगे कि कोई भी फ्लड इन्डिया के अन्दर ऐसा नहीं था जोकि सात दिन से ज्यादा रहा हो । तो क्या मिनिस्टर साहब कोई स्कीम नहीं बना सकते हैं जिससे कि उस पानी को डिटेन करके यूटिलाइज किया जा सके ।

अब जहां तक बिजली की बात है, इन्होंने एक ग्रिड सिस्टम स्टार्ट कर दिया । उससे एक स्टेट की बिजली दूसरी स्टेट के दे सकते हैं । ग्रिड सिस्टम का उन्होंने एक प्लान बनाया लेकिन जो रीवर ग्रिड सिस्टम है या वाटर रिसोसेज सिस्टम के लिए क्या करने जा रहे हैं । जिस समय बाढ़ आती है, उस पानी को क्यों नहीं डाइवर्ट करते हैं ताकि जहां पर शार्टेज आफ वाटर है, वहां पर उनको यूटीलाइज किया जा सके । क्यों नहीं अन्डर ग्राउन्ड चेनल्स आप बनाते ताकि जो फ्लड आए उसको प्रिजर्व किया जा सके और समय पर यूटीलाइज किया जा सके ।

आपके रीवर्स की जहां तक बात है, इनके बेड्स डिफेक्टिव हैं । यहां पर चीफ इन्जीनियर साहब बैठे हुए हैं । अर्थ डेम आपके बिल्कुल बेकार हो चुके हैं । आप किसी अर्थ डेम को ले लीजिए । आफटर फिफटी इयर्स वह बिल्कुल डिफेक्टिव हो जाएगा और वह फ्लड्स नहीं रोक पाएगा क्योंकि उसके बेड पर सिल्ट हो जाएगी । तो क्या आप इस तरह का प्रोवीजन कर रहे हैं कि अर्थ डेम की बजाए कोई दूसरी चीज हो जिससे ये फ्लड्स रोके जा सकें ।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है, मैं अपने जिले की दो एक बातें कह दूं । हमारे जिले का हर किसान चाहता है कि उसे बिजली मिले जिससे वह तीन गुना, चार गुना, पांच गुना और दस गुना गल्ला पैदा कर सकें, लेकिन यह सरकार 22 साल के बाद और तीन पचवर्षीय योजनाएँ बनाने के बाद भी नाकाबिल रही है कि हर किसान को बिजली दे सके और हर किसान को पानी दे सके ।

श्री रणधीर सिंह : आप मिनिस्टर साहब को अपने जिले का नाम बता दें ?

श्री राम चरण : मेरा जिला बुलन्दशहर है जहां का हर किसान चाहता है कि उसको पानी समय पर मिल जाए, नहरे पानी दें । आपके जो सरकारी ट्यूबवेल्स हैं वे फेल हो चुके हैं । जिन लोगों ने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगा रखे हैं उनको भी बिजली नहीं मिलती है । और जो कुछ मिलती है वह रिश्वत के सहारे मिलती है ।

श्री रणधीर सिंह : जरूर मिलनी चाहिए ।

श्री राम चरण : अगर आप देश के किसान का भला चाहते हैं तो मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वे किसानों को पानी दें ।

रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन की एक बात और मैं कहना चाहता हूं । इन्होंने कहा है कि देहातों में बिजली पहुंचा रहे हैं । मैं आपको बताऊं कि जिन गांवों के अन्दर इन्होंने बिजली पहुंचाई

[श्री राम चरण]

है, वहां पर सिड्यूल्ड कास्ट के एरिया के अन्दर बिजली का एक खम्बा भी नहीं मिलेगा। 80 फीसदी गांवों के अन्दर यह जो बिजली है यह सिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के हक में नहीं है।

जहां तक ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की बात है, 80 फीसदी देश के गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी के साधन नहीं हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि इन्होंने अब एक स्कीम बनाई है। (समय की घंटी) मैं एक मिनट लूंगा। जो यह रूरल वाटर सप्लाई स्कीम बनाई है, तो क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जिस जगह पर पीने का पानी नहीं है, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्दर हर गांव में पीने के पानी का इन्तजाम करेंगे।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक पाकिस्तान और इन्डिया का सवाल है, यह इस तरह से लिंगर आन होने की जो बात है, यह डिस्प्यूट कब तक पाकिस्तान के साथ चलता रहेगा। यह क्या खिलवाड़ है। आपको चाहिए कि पर्मानेन्ट बेसिस पर आप इसको समाप्त कर दें और तय कर लें कि इतने परसेन्ट वाटर हम लेंगे और इतने परसेन्ट वे लेंगे, इतने क्यूसेक्स वाटर हम लेंगें और इतने क्यूसेक्स वे यूटीलाइज करेंगें और वह जो फैसला हो, उसका इम्पलीमेंटेशन हो जाए। और इन्टरनेशनल बेसिस पर उसका एग्रीमेंट हो जाए। आपने जो फरक्का प्रोजेक्ट बना दी तो पाकिस्तान की जबान ललचाने लगे। उसको पता है कि फरक्का बांध के बन जाने से इस देश का, भारत का कितना डेवलपमेंट होगा। तो क्या मन्त्री जी इन्टरनेशनल वाटर डिस्प्यूट के अन्दर इस तरह का प्रोवीजन करेंगे जिससे हमेशा के लिए यह सवाल हल हो जाए और इन्टरनेशनल कोर्ट के जरिये से हो।

अन्त में मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि हमारे यहां यू० पी० के अन्दर और खास तौर से पूर्वी इलाकों के अन्दर और बिहार के अन्दर उन एरियाज के किसानों को, जिनको स्केयरसिटी एरिया कहते हैं या जिसको फेमिन एरिया कहते हैं, वहां पर बाढ़ भी आ जाती है और छः महीने के बाद भुखमरी भी हो जाती है, पानी देने की व्यवस्था करें।

श्री यशवंतसिंह कुशवाह (भिंड) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई विभाग की जो मांगें पेश हुई हैं, उनका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कई वक्ता महानुभावों ने सिंचाई और बिजली मंत्री महोदय की इस आधार पर तारीफ की है कि वे तकनीकी व्यक्ति हैं। मैं भी उनकी तारीफ करता हूं कि उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त है कि वे इन्जीनियर हैं। लेकिन इन्जीनियर होने के नाते उनसे विभाग के कामों में अधिक क्षमता लाने की लोग आशा कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ठीक इसके विपरीत है। मैं उदाहरण के रूप में, उनके ही द्वारा दिये गये आंकों के आधार पर बताऊंगा कि सिंचाई विभाग की जो मौजूदा सिंचाई क्षमता है, मौजूदा स्थिति में उस क्षमता में केवल 50 फीसदी में सिंचाई हो पाती है अर्थात क्षमता क्षेत्र का 50 या 55 फीसदी ही केवल सिंचाई क्षेत्र हैं अर्थात वे उनकी क्षमता के आधार पर क्षमता से आधा ही काम करवा पाए हैं। उनके विभाग में लोग लापरवा हैं, इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जो मशीनरी नदी योजना के कामों के लिए खरीदी गई उसके बारे में उन्होंने अपने दिये हुए आंकड़ों में यह स्वीकार किया है कि 173 लाख रुपये की मशीनरी नष्ट हो जाएगी। केवल 30 लाख रुपये की मशीनरी जो टूटी फूटी हालत में है, ऐसी बची है जिसका उपयोग दूसरी योजना में किया जा सकता है।

लापरवाही के साथ साथ इनका डिपार्टमेंट घोर मौज करता है। इस मौज का उदाहरण यह है कि वह बहाने खोजा करता है कि किस तरह से हम विदेशों की यात्रा कर सकें। एक बहाना खोजा, रूस की यात्रा करने का, इनके डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारियों ने कि वहां जाकर तैराकी सीखेंगे। एक बहाना खोजा गया पैरिस की यात्रा का कि खुली नाली में पानी किस तरह जाता है, सफाई कैसे रखी जा सकती है इन बातों को देखें। इसी तरह से और बहानों से अनेक प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भेजे जाते हैं और इस तरह से पैसे का दुरुपयोग होता रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी तकनीकी तज्ञ व्यक्ति हैं तो उनके डिपार्टमेंट की क्षमता बढ़नी चाहिए जो मौजूदा सिंचाई साधन हैं उनसे सिंचाई का एरिया बढ़ना चाहिए, उनके विभाग की जो सम्पदा है, जो मशीनरी है, उसकी देखभाल ठीक रूप से, अच्छे ढंग से होना चाहिए और पैसे का दुरुपयोग उनके मातहत उनको आंखों में धूल डालकर न कर सकें, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

एक और बात उनकी लापरवाही की मैं बताना चाहता हूं और वह यह है कि, सभापति महोदय आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में विदेशी शासन के वक्त का 1910 का बिजली अधिनियम अभी तक चालू है और मिनिस्टर साहब को यह फुरसत नहीं मिली कि उस अधिनियम को आज की परिस्थिति में बना कर पेश कर सकते। जो बिजली उपयोग के लिए जो कानून है वह भी 1948 का है। उसके लिए भी यह जरूरी है कि आज की स्थिति के अनुसार उसमें संशोधन किया जाता, आज की स्थिति के अनुसार कानून लाया जाता। लेकिन उसके लिए भी मंत्री महोदय को जरा सी भी फिक्र नहीं हो रही है।

मैं इस बात की तारीफ जरूर करना चाहता हूं कि स्वराज्य होने के बाद से हमारे देश में सिंचाई का ऐरिया बढ़ा है। जहां 1951 में 56 मिलियन एकड़ भूमि क्षेत्र सिंचित होती थी अब 1968 में सिंचित क्षेत्र बढ़ कर 67 मिलियन एकड़ हो गया है लेकिन केवल इतने से ही हमें संतोष मान कर बैठ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भगवान की देन के रूप में हमें जो पानी मिलता है उस पानी का केवल 37 फ़ीसदी ही हम उपयोग करवा रहे हैं। दो तिहाई पानी हमारा बह कर समुद्र में जा रहा है लेकिन उस पानी को रोकने की और हमारी ज़मीन को हरा, भरा करने की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी उन में बड़ी नदी योजनाएं 534 अपनाई गई। उन 534 में से सिर्फ 318 योजनाएं अभी तक पूरी हुई हैं और लगभग आधी योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। उन योजनाओं के पूरा होने की जो एक अवधि नियत होती है कि अमुक योजना इतने काल में पूरी हो जायेगी वह समय बराबर द्रोपदी के चीर की तरह से बढ़ता जाता है साथ ही खर्चा भी बढता जाता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं होती है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि हमारा प्रदेश अर्थात् मध्यप्रदेश क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सब से बड़ा प्रान्त है लेकिन जो 534 योजनाएं सारे देश में अपनाई गई उस में से मध्यप्रदेश के हिस्से में केवल 4 योजनाएं दी गई हैं और उन चार में से एक भी अभी तक पूरी नहीं हुई है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ध्यान सिंचाई योजनाओं में से छोटी सिंचाई योजनाओं की तरफ जाना चाहिए जिससे हम थोड़े पैसे में अधिक लोगों को फायदा पहुंचा सकें। हमारे मध्यप्रदेश में खेती के लिए ज़मीन बहुत अधिक उपलब्ध है लेकिन सिंचाई के साधन न होने से उत्पादन नहीं बढ़ता है। अगर उस प्रान्त को सिंचाई के साधन देने के मामले में प्राथमिकता दी जाय तो मैं दावे के

[श्री यशवन्तसिंह कुशवाह]

साथ यह अर्ज कर सकता हूं कि मध्यप्रदेश इतना अनाज पैदा कर सकता है जिससे कि सारे देश को अन्न का भंडार मिल सके। और जाहिर है कि फिर विदेशों से अन्न मंगाने की आवश्यकत नहीं रह जायेगी।

लघु सिंचाई योजनाओं के लिए ट्यूबवैल्स की बात कही गई है लेकिन ट्यूबवैल्स की बात जहां कही जाती है वहां यह भी तो सोचना चाहिए कि हमारे वह ट्यूवैल्स जोकि हम योजनाओं में आंकड़ों के रूप में रख तो लेते है लेकिन वह तैयार नहीं किये जा सकते क्योंकि हमारे देश में रिग जोकि ट्यूबवैल्स के लिए आवश्यक है उन को बनाने या प्राप्त करने के लिए सुविधा नहीं दी जा रही है। हमारे प्रान्त में कोई 7000 ट्यूबवैल्स लगेंगे। यह बात भी उस में कही गयी है कि केन्द्रीय शासन, के सिंचाई ऐक्सपर्ट्स की राय है कि वह 7000 ट्यूबवैल्स जोकि मध्यप्रदेश में मिलेगे उस में से भिंड जिले को सबसे पहले मिलने चाहिए क्योंकि वहां इस की सफलता की सम्भावनाएं सब से अधिक है। लेकिन खेद का विषय है कि भिंड जिले मे 7000 में से एक भी ट्यूबवैल का काम अभी तक प्रारम्भ भी नहीं हुआ है। किसी ऐसे अधिकारी के दर्शन तक नहीं हुए हैं। यह सूची तक नहीं बनी है कि किस किस गांव में वह ट्यूबवैल्स लगेंगे ? इस तरह से केवल मात्र योजनाएं बनाने से काम नहीं होता है बल्कि उस में देखना चाहिए कि क्या क्या सहूलियतें आवश्यक होंगी। ये बातें मैं आप के माध्यम से मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

एक बात जोकि मैं बड़ी योजनाओं के सिलसिले में कहना चाहता हूं वह यह है कि मंत्री जी बड़े सक्षम हैं पर अगर सचमुच में वे हल्की बातों से ऊपर उठ कर काम करने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है।

एक उदाहरण हमारे यहां की नर्मदा नदी की योजना है। लम्बे समय से इस योजना के लिए कई प्रोजैक्ट मंजूर हुए हैं लेकिन न तो उस के लिए पैसा मिलता है और न ही उन को काम प्रारम्भ करने दिया जाता है। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश का समझौता होने के बाद भी जल सिंधी योजना का काम शुरू नहीं करने दिया गया। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कि मंत्री जी को ऊपर उठ कर तय करना चाहिए। नीचे की ओर बहने वाले पानी के बटवारे के विषय में यह जो उनकी अपनी आवश्यकता है, उन के प्रान्त की जरूरत हो सकती है, उनके क्षेत्र की हो सकती है परन्तु उस के लिए दूसरे प्रान्तों के साथ अन्याय न हो यह देखना भी उन का फर्ज है।

माननीय मंत्री जी के विभाग में एक काम भू संरक्षण का भी आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 13 नदी घाटी योजनाएं तीसरी पंचवर्षीय योजना तक थीं और 14 नदी घाटी योजनाएं और नई लेने की है। अब तक कोई 9 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो चुका है लेकिन उस का फायदा कहीं भी दिखाई नहीं देता है। मैं एक ऐसे एरिया, एक ऐसे क्षेत्र के बारे में अर्ज करना चाहता हूं जोकि एक समस्या प्रधान क्षेत्र है, चम्बल नदी क्षेत्र जोकि भिंड, मुरैना जिले में है वहां ज़मीन कटती जा रही है, ज़मीन बराबर ढह कर पानी के साथ बह कर जा रही है और कम होती जा रही है। वहां डाकू लोग शरण पाते हैं, गहरे गहरे गडढे हो गये हैं उस का संरक्षण करने की आवश्यकता थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा पाएलट योजना बना कर परीक्षण भी किया गया। लेकिन उसके बाद वह पैसा खत्म हो गया और वहां अब कोई काम नहीं हो रहा है। उस क्षेत्र को प्राथमिकता इसलिए दी जानी चाहिए ताकि यह डाकू समस्या का निदान हो जाय। वहां किसानों के पास जो एक जमीन है दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा यह औसतन बहुत कम

है। जनसंख्या वहां सब से ज्यादा है। जबकि दूसरे प्रान्तों और दूसरे हिस्सों की अपेक्षा गरीबी बेहद बढ़ी हुई है। अगर इन नदी योजनाओं में भू संरक्षण का जो काम होना है उस में भिंड, मुरैना जिले के चम्बल वाले एरिया को प्राथमिकता दी जायेगी तो मंत्री जी उस क्षेत्र की बड़ी सेवा कर सकेंगे और डाकू समस्या के रूप में वहां जो एक आतंक फैला हुआ है उस आतंक को भी समाप्त करवाने में सहायक बन सकेंगे।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमारे देश में बिजली का उत्पादन बढ़ा है लेकिन उस के बाद भी इस बात को स्वीकार करने में मंत्री जी को इंकार नहीं होगा कि दूसरे जो प्रगतिशील देश हैं उन की तुलना में आज भी भारत के प्रति व्यक्ति का जो विद्युत का खर्चा है वह अत्यन्त नीचे का आंकड़ा है और उस आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है और मंत्री जी को बहुत काम करने की जरूरत है तभी वह सिद्ध कर सकते हैं कि वह एक सक्षम प्रशासक भी हैं।

बिजली गांवों को भी दी जाये इस के लिए प्रचार तो बहुत होता है। हम गांवों को भी बिजली दे रहे हैं इस के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं लेकिन दे किस तरह से रहे है? भारत जोकि 7 लाख ग्रामों का देश है उस में अभी 20 साल के भीतर 57000 या 60,000 यह दो तरह के आंकड़े हैं अब सच्चे आंकड़े कौन से हैं यह वह जानें लेकिन ज्यादा वाला भी हम मान लें तो उस के मुताबिक 60,000 ऐसे हैं जिन्हें कि इन आंकड़ों के आधार पर 20 साल में बिजली दी जा सकी है। औसतन अगर देखें तो यह मानना पड़ेगा कि जिस रफ्तार से यह कार्य चल रहा है उसी रूप से चलता गया तो बहुत से गांव ऐसे रहेंगें जिनको कि 200 वर्ष बाद जाकर कहीं बिजली मिल सकेगी। 200 वर्ष तक यह सारे देश को बिजली देने का काम पूरा नहीं कर सकेंगें। भारत जोकि एक कृषि प्रधान देश है भारत जोकि गांवों में बसता है, क्या वह देश 200 वर्ष तक रावसाहब से बिजली पाने के लिए इंतजार करता रहेगा? फिर अभी तक जिन गांवों में बिजली दी जाती है वहां उस में केवल चंद प्रकाश के लट्टू लगा दिये जाते है और बिजली न गृह उद्योगों के लिए मिलती है और न ही सिंचाई के लिए मिलती है। इसलिए मेरी अर्ज है कि बिजली देते समय गांवों को प्राथमिकता देनी चाहिए और वहां सिंचाई और गृह उद्योग को अधिक से अधिक बिजली मिले इस के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि जहां जहां बड़ी पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर बिजली उत्पादन का काम हो रहा है उन सब का अगर एक ग्रिड बना दिया जायेगा तो देश में हम ज्यादा सेवा कर सकेंगे। मुझे जो समय दिया गया उस के लिए मैं आभार प्रदर्शित करता हूं।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : Sir, I would like to raise only two or three points. As the hon. Minister, Dr. K. L. Rao, very well knows, in Tamilnadu we do not have many river water sources, either major or medium. Fortunately, we have thousands of small lakes and tanks about which we prepared a scheme costing about Rs. 100 crores. Unfortunately, the Irrigation and Power Ministry now tell us that this is not a subject with which they are concerned, as it comes within the province of the Ministry of Food and Agriculture. But the total allocation of the Agriculture Ministry under this head is so meagre that even if they give a major portion of the allocation it would not touch even a fringe of the problem we are facing today. This is the dilemma for us-this is the only major source of irrigation for us available within the state and neither the Irrigation Ministry nor the Agriculture Ministry would help us to tap or improve this potential. So, I would only ask Dr. K. L. Rao to take up this issue with the Minister concerned and also with his Government and

[Shri Kandappan]

see that the only possibility that is there in Tamil Nadu gets some assistance from the Centre.

16 hrs.

Then, I would like to place one more thing for his consideration. I would like to remind Dr. K. L. Rao that he was directly concerned in that project of the former composite Mad as State. There was an investigation project considered by the name of Ramapadasagar project. Shri Tenneti Viswanatham and other Members who happened to be there at that time in the Assembly might be knowing about it. That was with regard to having a dam across the Godavari river and diverting the waters into the Krishna river and from the Krishna taking it to the North Pennar and from there diverting it to either Veeranam lake or the Cauveri river. That was prepared as a major project and about Rs, 150 plus Rs. 70 crores were envisaged for that. I understand that at that time there was dispute between the engineers in my State headed by Dr. K. L. Rao and the Central Government, and it seems that the engineers in the State wanted to execute the programme on their own whereas the Central Government came in the way and they said that they would execute the programme. For this statement of mine, I am relying on the authority of an old Congressman who has recently written an article over this issue. It seems that Dr. K. L. Rao at that time was presiding over this affair. Even today, unfortunately, the waters of the Godavari and some other rivers in Andhra Pradesh are not being fully utilised. I think, subject to correction that only 20 to 30 per cent of the water availability is being utilised today. If the Central Government could seriously take up a programme of this magnitude in consultation with the Andhra Pradesh Government and the Tamilnadu State Government-of course, the Tamilnadu State can also be asked to share some of the financial involvement since that State would also benefit out of this scheme-that would be a good scheme which would cover a lot of area in that Andhra and Tamil Nadu belt. This is another suggestion that I would like to make to the hon. Minister and I hope he will consider it.

Some hon. Members have raised the issue of raising the rank of our hon. Minister Dr. K. L. Rao. I think the House and the country would appreciate if he is given a Cabinet rank; there is no doubt about it. This only goes to show the scant regard that the Central Government has got for irrigation and its importance for the country. That is how I look at it. It is precisely because of this attitude of the Government that I feel even the justification for a department at the Centre in this regard is not fully respected. When we look at the Gandak and Kosi projects, what do we find ? This morning, the report on the Gandak project was submitted. It would be very interesting to note that they had constructed a canal on the Bihar side hoping that the Gandak waters would flow into it, before the western portion of that canal on the UP side was not taken up.

SHRI BISHWA NATH ROY (Deoria) : On the UP side also, the work has been going on. The hon. Member seems to have got wrong information.

SHRI S. KANDAPPAN : The Bihar portion was completed two years back, but the UP portion was still to be taken up. The result is that the money that was invested on the Bihar portion of the Canal was wasted and became infructuous. The Centre which was all along dealing with this issue was not able to coordinate probably because they were not able to command the respect of the states. If this is going to be the situation in regard to such a vital and important portfolio like irrigation in our country I fear that things cannot improve very much in the near future. I hope that Dr. K. L. Rao with all the support that he can muster in this House would put up a brave fight and see that there is some improvement in irrigation in the near future in our country.

16. 04 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, Shri Brij Raj Singh-Kotah, he will have only two minutes.

SHRI BRIJ RAJ SINGH Kotah (Jhalawar) : I am very grateful for the kind privilege given to me to speak for two minutes. I would like to draw the hon. Minister's attention to the acute problem in our area namely the Chambal-commanded area as far as waterlogging is concerned. There is a pilot project working there for irrigation, drainage, land shaping and land reclamation. According to the official figures given by Government, the level of water table rising up from O to 5 feet, that is, up to the root zone of the crops, was for 44,000 acres in June 1968. From O to 10 feet, the area was 3,22,000 acres in the Chambal-commanded area of Rajasthan.

This problem is most acute and because of this waterlogging production has gone down. Salts have come up and all the resulting ills that are there have cropped up. Orchards by the hundreds and trees by the thousands, mangoes and citrus trees etc., which used to grow here so profusely, have now withered away.

I am told that this pilot project which was doing excellent work is under the Government of Rajasthan and that they have not sanctioned further funds for it. I would request and urge upon the hon. Minister that he will see that this project continues the work it is doing. There is such a lot of work to be done. If I were to narrate everything here, I do not think I would have the time to do justice to it.

As the hon. Member, Shri Kushwah, was saying, the Chambal ravines are a problem by themselves. They start right down from Kotah and end up where the river meets Etawah. Your department is trying to relcaim the land. It says that the cost of reclamation will come to Rs. 100 an acre. We also have a town called Etawah in the district of Kotah and their experience has shown that the reclamation charges are no less than Rs. 500 an acre and this area alone would need at least Rs. 30 crores to make the land arable.

So, with very limited time at my disposal, I would only request the hon. Minister to see that the acute problem of waterlogging is tackled, that the pilot project which is working in Kotah and which has four pilot demonstration projects--two in Bundi District and two in Kotah District--are made to work and that he takes serious note that if reclamation has to be done it has to be tackled on a real, wide national sale. That is all I have to say.

MR. DEPUTY-SPEAKER : A number of hon. Members could not get an opportunity and this is a debate in which every State and every region is interested. So, I will permit a few questions, Shri K. N. Pandey.

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : मेरा नाम कांग्रेस की लिस्ट में था, मुझे नहीं बुलाया गया ।

MR. DEUPTY-SPEAKER : I have got to see that all regions get an opportunity as far as possible; otherwise; it is not possible to manage, because this is a subject in which every State is interested. I will permit you one question.

SHRI BISHWANTH ROY : There is no question of putting questions...(*Interruption*)

SHRI ONKARLAL BOHRA (Chittorgarh) : Rajasthan has not been represented. वहां के लोगों को इसका मौका दिया जाना चाहिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : An independent Member has made the contribution. I must see that all sides are represented.

SHRI ONKARLAL BOHRA : The Congress Party list of speakers was given and there were two or three names in it from Rajasthan.

श्री रमेशचन्द्र व्यास (भीलवाड़ा) : जब से मैं इस सदन का सदस्य बन कर आया हूं, तब से मुझे एक शब्द भी बोलने का अवसर नहीं दिया गया है । कल से इन्तजार में बैठा हुआ हूं । फिर मैं आज का सदस्य नहीं हूं । जब आप विरोधी दल में बैठते थे, तब भी मैं कांग्रेस का सदस्य था । लेकिन इतना पुराना

[श्री रमेशचन्द्र व्यास]

सदस्य होने पर भी आप ने मौका नहीं दिया। राजस्थान के दो राजाओं को आप ने मौका दिया....

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is their time, What can I do ?

श्री रमेशचन्द्र व्यास : लेकिन मुझ को मौका मिलना चाहिये। यह मेरे साथ ज्यादती है और मैं वाक-आउट करता हूं। आप कांग्रेस वालों को भी चुन-चुन कर मौका देते हैं।

16.09 hrs.

(SHRI RAMESH CHANDRA VYAS ; then left the House.)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : Sir, it is with profound regret that I wish to bring to your notice that speakers mentioned in the list supplied on behalf of the Congress Party for your great consideration in calling speakers, according to reports received by me, have not been called to speak. I seek your indulgence and assistance because I have also a duty to discharge to my party.

MR DEPUTY-SPEAKER : Your time is so limited that if I had followed the serial list some of the States would never get a chance. For instance, the representative from Kashmir would never get a chance and he has something to say. If someone from the Opposition pleads the case of Rajasthan and then I bypass Rajasthan and call someone from, say, Mysore, I think, I am doing justice I would assure the Minister of Parliamentary Affairs that normally we take guidance from the list. But if it is expected that every time we are to follow it, it would not be doing justice to the debate and to the States.

There is another factor.

There are Members who never get an opportunity to participate in the debate. About Shri Randhir Singh, almost on every national debate, he participates. I cannot single him out. Therefore, if there is anything, I would suggest that if in respect of certain Members who never get an opportunity--it is possible I might slip over them-the whips point out to me that this is the case, I will, certainly, accommodate them. But normally, on national debates of this nature, accommodation must be made. You will appreciate my concern...

SHRI ONKARLAL BOHRA : Mr. Vyas has not spoken for the last 15 years.. (*Interruptions*)

SHRI BISHWANATH ROY : I did not get a chance to speak on the Railway Budget, the General Budget and the President's Address even though my name was given by the Whip. Again, this time, I did not get a chance even though my name was given.

SHRI RAGHU RAMAIAH : I appreciate your difficulty, Sir. But I would like you to appreciate our difficulty also. In preparing the list. we do take into account whether each State has been represented or not and whether each Member has spoken or not. We do not do it recklessly. We give consideration to that. If, after that, we find none of the names are called or called in such a manner that we ourselves are misunderstood in our party. I seek your indulgence for guidance, help and assistance.

MR. DEPUTY SPEAKER : If it is insisted that I call them serially, I will not be responsible because I will not be doing justice to the House. Yesterday, for instance the names that I incorporated were from a distant area, from Centrally-administered areas. They get only once in a while an opportunity to ventilate their grievances. Even going out of the way, I gave them an opportunity. I think, that is fair. But I appreciate your difficulty. We can try to solve it in a way that no injustice is done to anyone.

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : मुख्य कठिनाई तो यह है कि समय कम दिया गया है।

MR. DEPUTY SPEAKER : That is the main difficulty. What can I do ? You should fight for more time in the Business Advisory Committee meeting. Every time, I cannot extend time. I have discretion to extend time for half an hour only. In the Business Advisory Committee, your representatives are there and the Minister of Parliamantry Affairs is also there. We can adjust time. But every time, we are extending time. This is a subject in which every region, all the rural areas, is interested. I know how many slips I have got. I cannot help it. I will permit only a few questions.

SHRI K. N. PANDEY (Padrauna) : The hon. Minister has full knowledge of the grave situation caused by the Bari Gandak flood. I am thankful to him that he visited the area twice. Now, the flood has gone to such an extent that there is even a danger that the line between Chitoni and Khada will also be washed away. May I know what steps he is going to take to see that before the rainly season starts, the area may be saved from floods.

SHRIMATI JYOTSNA CHANDA (Cachar) : May I know from the hon. Minister what progress has been made in regard to the Barak project and whether he is going to include it in the Fourth Plan.

श्री ओंकार लाल बोहरा : मैं एक विशिष्ट प्रश्न की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए पोंग बांध बनाने का निश्चय किया है और सन् 1972 तक आप उस बांध को समाप्त करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस में साठ प्रतिशत रुपया राजस्थान का लगेगा और 47 प्रतिशत हरियाणा और पंजाब का। राजस्थान सरकार ने वायदा किया है कि इस पोंग बांध के अन्दर जो तीस हज़ार लोग विस्थापित होंगे उनको राजस्थान में जगह दी जाएगी और सवा तीन लाख एकड़ ज़मीन उनको राजस्थान में खेती के लिए दी जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप राजस्थान नहर को बनाने का फैसला नहीं करेंगे तब तक इस पोंग बांध से राजस्थान को कोई फायदा नहीं होगा। इसका कारण यह है कि पोंग बांध का पानी राजस्थान नहर को तभी मिल सकता है जब राजस्थान नहर पहले बने। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पोंग बांध के साथ यदि आपने राजस्थान नहर का साथ साथ निर्माण नहीं किया तो उसका नतीजा यह होगा कि न पोंग बांध बन सकेगा और न राजस्थान नहर। इस वास्ते मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान नहर को भी आप साथ साथ समाप्त करेंगे, उसको भी साथ साथ पूरा करेंगे ?

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): This is about Neiveli Corporation's power distribution to the neighbouring States. Recently the Committee on Public Undertakings has remarked severely against the execution of the Neiveli Corporation's power distribution to the neighbouring States. The Committee does not consider it desirable that the Corporation should think of dealing with one party alone, namely, the Madras State Electricity Board, instead of asking for the requirement of all the neighbouring States and distributing power equitably among them at the same cost. The Madras State Electricity Board is purchasing from Neiveli at the cost of Central Government, four Paise or five Paise, and they are selling that to the neighbouring States at a higher cost. I would request the hon. Minister to clarify the position of the Government of India and the action to be taken to implement the recommendation of the Committee on Public Undertakings.

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya) : I would like to pose the war of nerves that is going on between Dr. Rao and Mysore, with particular reference to a project known as 'Hemavati project' in the Cauvery Basin. Our agreement with Madras is up for renew and reconsideration in the year 1974 or 1972. But Dr. Rao has not so far given the clearance for Hemavati project--deliberately or for any other reason, I do not know. The Government of Mysore have made repeated attempts and they have made repeated trips to Dr. Rao to get the clearance

[Shri S. M. Krishna]

for Hemavati project. I would like to ask Dr. Rao what prevents him from giving clearance to this project.

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : सिंचाई योजनाओं को तीन भागों में विभक्त किया गया है। एक तो सिंचाई विभाग है, एक बिजली विभाग है और तीसरे छोटी सिंचाई योजनायें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन तीनों विभागों को एक ही विभाग के अन्तर्गत करने का क्या कोई प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका परिणाम यह होता है कि जो गलतियां इन से होती हैं, उनको पकड़ा नहीं जा सकता है। छोटी सिंचाई योजनायें कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आती हैं, बड़ी सिंचाई योजनायें इनके अन्तर्गत आती हैं और बिजली विभाग दूसरे विभाग के अन्तर्गत आता है। चूंकि इन तीनों का बटवारा आपने किया हुआ है इस वास्ते सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जहां पानी नहीं पहुंच रहे हैं वहां फर्टिलाइजर भिजवा दिया जाए ?

श्री शिंकरे (पंजिम) : मैं गोआ से आता हूं। वहां 125 इंच बरसात होती है। लेकिन वह सारा पानी समुद्र में चला जाता है। हमारी गोआ महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पक्ष की गवर्नमेंट ने सजैस्ट किया था सैंटर को कि वहां तीन योजनायें चल सकती हैं। उसमें जहां तक सेलावली योजना का सम्बन्ध है इससे तो केवल गोआ का ही सम्बन्ध आता है। लेकिन जहां तक सेलावली को छोड़ कर अन्य दो योजनाओं का सम्बन्ध है अर्थात तिल्लारी और हिरण्यकेशी प्राजैक्ट्स. इनको महाराष्ट्र सरकार के सहकार के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि चौथी योजना में आप इन में से कौन सी प्राजैक्ट को हाथ में लेने जा रहे हैं।

दूसरा प्रश्न मेरा बिजली के बारे में है। हमें अभी कोयना महाराष्ट्र और शेरावती (मैसूर) से बिजली मिलती है। वह बहुत मंहगी पड़ती है। गोआ जैसा छोटा सा प्रदेश इतनी मंहगी बिजली ले कर काम नहीं चला सकता है। फिर एक बात यह भी है कि वहां से जो बिजली आती है, उसकी जो लाइनें आती हैं वे पर्वतीय इलाके से आती हैं। जब बरसात होती है तब ये जो लाइनें हैं ये खराब हो जाती हैं और बिजली खंडित हो जाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे यहां गोआ में जो दूधसागर फाल है, वाटर फाल है, क्या उसको हमेशा टूरिस्ट्स के आकर्षण के लिए ही रखा जाएगा या दूधसागर फाल का बिजली उत्पादन के लिए भी उपयोग किया जाएगा ? बीस साल पहले जब वहां पौरचुगीज गवर्नमेंट थी तब उसने स्वर्गीय विश्वेश्वरैया जैसे प्रख्यात इंजीनियर को बुलाया था और उन्होंने उसका सर्वे किया था और एक योजना भी दी थी। उस वक्त भी वहां की सरकार चाहती थी कि इसका बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका जल्दी से जल्दी सर्वे किया जाएगा और इस योजना को हाथ में लिया जाएगा ?

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (मलेमपुर) : मैं एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न की ओर सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह सौभाग्य से बहुत ही कुशल इंजीनियर भी हैं। गत वर्ष वह बलिया जिले में गए थे और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से बलिया जिले और देवरिया जिले में दो भयंकर नदियां बहती हैं गंगा और घाघरा।

बड़े बड़े सुन्दर गांव और कस्बे इन दोनों नदियों के कटाव के अन्दर हैं। जब सिंचाई मंत्री महोदय बलिया पधारे थे, इन्होंने वचन दिया था–घाघरा नदी के किनारे जो गांव कटाव में हैं, बलिया और देवरिया जिले में, उन

का संरक्षण करेंगे और संरक्षण कर के ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि वे गांव कटाव से वंचित हो जायं। मैं जानना चाहता हूं कि घाघरा नदी के किनारे और गंगा नदी के किनारे के जिन गांवों के प्रति इन्होंने विश्वास दिलाया था, उन के बचाव के लिये इन्होंने कौन सा काम किया है, उन का संरक्षण किया है या नहीं ? यदि नहीं किया है तो कब करने वाले हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, पटना बिहार की राजधानी है, आप जानते हैं, मंत्री महोदय भी जानते हैं। मैं उसी के सिलसिले में पूछ रहा हूं। पटना में अक्टोवस द्वारा कम्पनी संचालित पटना इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है और दूसरा वहां पर बिहार बिजली बोर्ड है। बिहार बिजली बोर्ड का बिजली रेट कुछ है और उस से ज्यादा रेट पटना इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने रखा है। किसानों को ज्यादा रेट पर पानी देते हैं, जिसको लेकर हाई कोर्ट में कुछ मुकदमें भी चले। वहां के लोगों ने बार बार मांग की है कि बिजली का रेट ज्यादा होने से वहां के उद्योग धन्धों के विकास में गड़-बड़ हो रही है, किसानों को सिंचाई के लिये ठीक से पानी नहीं मिलता है। पटना इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी और उसी तरह की दरभंगा इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को सरकार अपने कब्जे में ले ले, ताकि वहां पर जो दो रेट चल रहे हैं बोर्ड का अलग और कम्पनी का अलग-वे समान हो सकें। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस के बारे में क्या विचार कर रही है ? सरकार जल्द से जल्द इन को अपने कब्जे में ले ताकि वहां की जनता की आशा और आकांक्षा पूरी हो सके और पटना इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की मनमानी और लूट खत्म हो सके।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा इलाका गंगा और घघर दोनों से कट रहा है, जिसको राष्ट्रपति शासन काल में हमारे इन्जीनियर्स देख आये हैं। अगर उस में अप्रैल तक काम नहीं हुआ तो बलिया का दो-तिहाई हिस्सा डूब जायेगा, इस से 20 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। भारत सरकार और यू० पी० सरकार के जो इन्जीनियर्स वहां गये थे, उन्होंने एक योजना बनाई थी, जिस पर डेढ़ करोड़ रुपया खर्च होने वाला था। अब केन्द्र सरकार यह कह रही है—कि तुम्हारे यहां सरकार बन गई है, इस लिये अब तुम अपनी सरकार से बात करो। हमारा यह कहना है कि पटेल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हमारा जिला बैकवर्ड माना गया है, उस के विकास के लिये सारा काम भारत सरकार के सुपुर्द है, इस लिये भारत सरकार को उस पर काम करना चाहिये।

श्री बेनी शंकर शर्मा (बांका) : मैं माननीय मन्त्री का ध्यान बड़ुआ डैम की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां दो नहरें हैं - एक पश्चिमी और दूसरी पूर्वी। पश्चिमी नहर 20 फुट नीची है और पूर्वी नहर 20 फुट ऊंची। जो पूर्वी नहर है उस में 75 प्रतिशत कमाण्ड एरिया है और पश्चिमी नहर में 25 प्रतिशत कमाण्ड एरिया है, इस तरह से पूरब की नहर ऊंची होने के कारण 75 प्रतिशत कमाण्ड एरिया वाले इस क्षेत्र को पानी नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों नहरों का लेवल एक किया जाए। गत वर्ष भी मैं ने इस प्रश्न को सदन में उठाया था और माननीय मन्त्री डैम पर गये भी थे और उन्होंने अपने मातहत इन्जिनियरों को कुछ डाइरैक्टिव्ज भी दिये थे। मैं जानना चाहता हूं कि उन के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है और उन दोनों नहरों के धरातल को समान किया जा रहा है या नहीं ?

दूसरे—चान डैम करीब करीब बन गया है, लेकिन जो नहर उस से निकलने वाली है, उसके लिये कहा गया है कि अभी तक टैकनीकल क्लियरैंस नहीं दिया गया है। मैं जानना

[श्री बेनी शंकर शर्मा]

चाहता हूं कि यह क्लियरेंस कब तक दे दिया जायेगा, क्योंकि डैम बन गया है, किन्तु नहर नहीं बनी ऐसे डैम से क्या फायदा होगा ।

DR. P. MANDAL (Vishnupur): There was unimaginable and unprecedented, devastating flood in the North Bengal in 1968. The Prime Minister and the Deputy Prime Minister visited North Bengal and they declared then and there that finance will not be a hurdle for rehabilitation and hydro-electric power schemes. But till now the affected people were not rehabilitated and the power project also not completed. In the Farraka Barrage project the controversy arose over the question of submersible cellular coffer dam. Some local engineers felt that such a method would not work in alluvial rivers in monsoon areas where fluctuations of the water level is very much between flood months and dry months. A number of Russian experts were brought in. They strongly supported the idea that submersible Cellular coffer dam will work satisfactorily. Since some of the engineers still maintained that such a system would not work in the central part of the river it was decided that some cells would be put up in the river. Trial cells were accordingly put up at a considerable expense and a large quantity of cellular coffer dam piles were also purchased for the main works in anticipation of the method proving successful. But after the first floods it was found that the cells were not there. They had to be found out by magnetic surveys below the river. It is a mere wastage of foreign exchange. I want to know what is being done in this regard.

The Kangsabati project has been taken up in the 2nd Five-year Plan and not even one third of the work has been completed. If it is completed it will irrigate 8 lakh acres of land and save the lower Midnapore from flood. It was a scheme costing Rs. 22 crores. Because the project has been delayed it has cost Rs. 50 crores. May I know whether sufficient funds will be allotted to complete the work ?

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati): I want to ask only one question. This is about the Kapilli Valley Project. It is a multipurpose project in Assam. It has got three-fold purpose. One is flood control; the second is irrigation and the third is power generation, for which the Government of India and State Government have spent some crores of rupees. Uptill now the plan has not yet been executed. The Government of India has not given any help in the implementation of the national project. I want to know from the Government whether the Government of India will give clearance soon to this project.

श्री मीठा लाल मीना (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के उत्तरी भाग में जिस प्रकार सरकार ट्यूब-वैल बना रही है, ऐसी ही व्यवस्था दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भी होनी चाहिये । वहां के किसान उस का खर्च स्वयं वहन करने के लिये तैयार हैं, लेकिन पहला ट्यूबवैल सरकार लगाये, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि ये ट्यूब-वैल सफल होंगे या नहीं । अगर पहला ट्यूबवैल सरकार लगा कर बतला दे, तो आगे के लिये वे उस का खर्च किसान स्वय वहन करने को तैयार हैं । मैं यह सुझाव राजस्थान के सवाई-माधोपुर जिले के लिये दे रहा हूं । क्या सरकार इस तरह का ट्यूबवैल खोलेगी ?

किसानों को बिजली देने में वहां बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है । मैं चाहता हूं कि उस को दूर करने के लिये सरकार कुछ कदम उठाये ।

श्री भोलानाथ मास्टर (अलवर) : मन्त्री महोदय दिल्ली से अलवर हो कर जयपुर को बिजली की लाइन से जोड़ना चाहते थे । लेकिन राजस्थान सरकार कहती है कि इस को आल इण्डिया ग्रिड में ले लिया जाये और वह कर्जा हमारे नाम अभी डाल दिया जाये—अगर ऐसा आप कर दें तो उस को वह मन्जूर करने के लिये तैयार हैं । राजस्थान सरकार इस समय 40 करोड़ रुपया फैमीन पर खर्च कर रही है,

इस लिये वह पैसा अपने खर्च में डालने के लिये तैयार नहीं है । मैं चाहता हूं कि आल इण्डिया ग्रिड में पहले से ही कर्जा राजस्थान के नाम डाल कर जयपुर से दिल्ली को जोड़ दिया जाये ।

श्री रमेश चन्द्र व्यास (भीलवाड़ा) : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं—पौंग डैम 1972 तक पूरा हो जायेगा, लेकिन उस के लिये नहर बनाने के वास्ते पैसा नहीं है । उस में डूबने वाले जितने भी हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, उन को राजस्थान में बसाने का जिम्मा लिया गया है, लेकिन अगर वहां पानी नहीं जायेगा तो वे कैसे बसेंगे । इस लिये मैं चाहता हूं कि नहर बनाने का खर्च राजस्थान सरकार की मांग के अनुसार दिया जाना चाहिये ।

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डा० राव से जानना चाहता हूं कि कोल्हापुर जिले में जो एक दूध गंगा प्रोजेक्ट है जिससे कि डा० राव भी स्वय काफी वाकिफ हैं कि वह बहुत ही फायदे मन्द प्रोजेक्ट हैं-वहां पर एक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी भी शुरू हो गई है जिसको कि इसी आधार पर इजाजत मिली थी कि वहां पर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है-और वह इलाका भी बहुत पिछड़ा हुआ है, तो क्या उस प्रोजेक्ट को आप चौथी योजना में स्थान देंगे ?

MR. DEPUTY SPEAKER : Now I will call the Hon. Minister. I have called members from almost all the States as far as possible.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : Not Haryana. I won't take much time. I would like to put a direct question. What about Rabi-Beas link ? 75 per cent of the water has to be diverted to Haryana from this link. Then, what about Bhakra-Nangal share for Haryana ? These Punjabi friends and brothers are not giving us anything. Finally what about the Kisau Dam and Gurgaon Canal? What about the unanimous resolution passed by the House regarding Sahibi Nadi ? I want all these to be implemented.

MR. DEPUTY SPEAKER : No more questions. We must set some time limit. I was trying to accommodate most of you. Yes, Shri Verma will be the last member to put the question.

श्री बाल गोविन्द वर्मा (खेरी) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरजू कराज प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है उसके बनने में कितने दिन लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, उससे निकली हुई नहरों से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और कितनी बिजली उससे पैदा की जा सकेगी ?

SHRI INDER J. MALHOTRA : No member has participated from Jammu and Kashmir.

MR. DEPUTY SPEAKER : Your member has got an opportunity. You were not here.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : I just want to know from the Hon. Minister whether the Mahanadi Delta irrigation scheme, for which already a scheme was prepared and forwarded to the Government of India, is going to be taken up this year and at what stage is that project now ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : One question.

MR. DEPUTY SPEAKER : No, please. You are a very senior member. Now the Hon. Minister.

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : Mr. Deputy Speaker, I must thank all the Hon. Members who have participated in this debate. I am very thankful for a large number of suggestions. There are some Hon. Members who are not quite happy. I quite appreciate that. It is because they are most anxious about the rapid and accelerated development both in the fields of irrigation and power.

[Dr. K. L. Rao]

First, I will briefly review some of the most important aspects of the questions Hon. Members have raised and then deal with some projects that they mentioned. But I am afraid that, with such a large number of questions that have been raised, it will not be possible for me to cover all of them within forty minutes and therefore to such of those questions that are left over, written answers will be sent.

First of all I would like to say about the question of target and achievement. In the field of irrigation, for example, the target this year is 2.2 million acres. That is we wanted to create a potential of 2.2 million acres. The actual achievement was 2 million acres. The reason for the non-fulfilment was that we could not finance the Mahanadi Delta scheme fully so that we lost one lakh acres there and another one lakh acres on other schemes. Therefore, on the whole, we have been able to do fairly well in the matter of achievement of target set for 1968-69.

Similarly, in respect of power, the target was 2 million kw. Actual achievement was 1.5 million. You may say that 0.5 million is a big amount. But it is not really a bad achievement.

The fact is this : when you have a target like this, it includes all the various types of generation of power. That is, in the 2 million kw. target is included atomic energy power. We expected from Tarapur 3.8 lakh kw., but it did not fructify. Tarapur was expected to be commissioned in October last year, but it was not done. Due to some reasons, they were unable to commission the station. We expect to commission it in May, by June completely. That means it will come nearly two months later. That was how the target set could not be achieved fully.

Then comes the question of what the targets should be for the future. Many hon. members were very particular that the acceleration in respect of irrigation and power should be very high. I entirely agree. In fact, in the field of power, our achievement was less than half a million kw till 1964. It is only in the last four years that we have raised it to 1½ million kw. a year. Consumption in the country of power is increasing and demands are bound to be great. According to the opinion of the Ministry, the target increase should be at least 2½ million kw. every year; it is only then that we will be able to deal with the growing and very heavy demand in the country. Then only will be able to do some justice.

Of course, as hon. members are aware, due to our limited financial resources, we are not able to expand it as we would like to. But according to our estimate, we should be able easily to achieve a target of 2½ million kw. every year.

As regards irrigation projects, we have on hand a large number of projects which had been taken up previously. They are in various stage of construction That is why we are not adding any further projects. Still our target next year will be 2.4 million acres. Though the money provided is not very large, because various projects are at various stages, some nearing completion, some in the process of construction and so on, we are going to add this much. Our target must really have been about 3 million acres addition every year. That really answers the needs of the nation. Three million acres in irrigation and 2½ million kw power every year will be the ideal targets that we should aim at, taking into account absolute minimum growth of the country.

Then hon. members mentioned about the all-India grid. I agree it must be achieved at the earliest. What we have now got is the framework of a grid. It is not complete, but I think in the next year we will be able to have the framework of an all-India grid. Today we have got power connection line from Amritsar to Calcutta completely. That is, we can transmit power from one end to the other. Similarly on the west coast, from Bhakra to Papanasam in the south, it is continuous except for a link between Kolhapur and Belgaum. If this link is completed, we will be able to transmit power from Bhakra to Papanasam uninterrupted. Similarly on the east coast, from

Papanasam to Calcutta, except for a line between Talcher and Macherla, it is complete. That is, you have got the triangle. You have got the Gangetic power line; you have got the west coast power line and the east coast power line, except for a few small links. We have got the line from Calcutta to Bombay nearly complete except for a gap between Hirakud and Korba.

Thus, we have got the framework of an all-India grid. But this has got to be strengthened to carry more power. For example, in the Bengal area, we are going to have very heavy consumption, and a 400 kv. line is necessary. We have got to have a tie-up. We estimate that the cost would be of the order of Rs. 40 crores. The Fourth plan is not finalised, so that we do not know what amount will be provided for power. With the result that the all-India grid-I am afraid-can be formed in an effective way only by the end of the Fifth Plan, although we have the capacity to do it much earlier, in the next five years.

In the matter of interlinking of rivers Shri Maharaj Singh Bharati and Durairasu and other hon Members have been telling often that the rivers of India must be linked and that Ganga must be linked with Cauvery. Last year also they said so. It has been a sort of a tradition handed over to us. I thought that this problem must be looked into. When I went to the United States about six months back, I saw schemes there which were very helpful in guiding my thinking on this matter. So, I made some studies in that respect. I want to warn the House that what I am placing before the House cannot be achieved tomorrow. It has got to wait until we become prosperous and more money could be found to finance the schemes and it has also to wait till the investigations are completed. I expect that any scheme like the one which I am going to outline before you will be taken up only at the end of this century. The scheme is roughly like this. One must always take water from where it is excess or surplus and at the time when it is surplus and is not needed. In the Ganga the only place where you can get such water is Patna and below. Above Patna Ganga waters are practically committed and used up. For four months in a year during the monsoon time when the discharge is heavy and the water cannot be used lower down, this water should be tapped at that point. I have done some preliminary studies and I find that if we take a canal from there by a series of lift systems, we can take water right through to Rihand and then Demba on Sone, going on to Bargi on the Narbada, and Pench in Maharashtra, Pochamad on Godavari and then go up the heights of Mysore-Maharashtra plateau, and then go down to Cauvery and lower down to Kanyakumari. That is a sort of a practical and possible alignment of the main feeder canal and from this canal we can take out tributaries and branches on either side to feed the arid regions in all the areas. The House must not take me seriusly. This is an idea which I am trying to explore further and it goes a little more than where it was last year. Hon. Members have provoked me into this kind of thinking. The great advantage of this link will be that there will really be integration; there is no doubt about it. There are river water dispute about the peninsular rivers merely becaus: of small marginal deficit amount of water, it is not huge amount of water that are involved and these marginal amounts can be provided by this feeder canal and those disputes also can be solved. One should think of the possibility of using the holy Ganga; after all Ganga is our sacred river and it is sacred to the whole country. It is quite possible for us to use the excess amount of water when there are floods in the Gangetic plains and it is possible for us to take it to areas lower down. But I must again caution that this is purely a sort of a paper study and has got to be investigated further. We will not be able to bear the cost because all the time we are lifting water and at some places we lift it to 1600 feet. This is not the time to do so. In America they are doing it now but we are not so prosperous; we must remember that. However, I am certain that at the end of this century India will not be what it is today and our children are going to be richer and more prosperous and at that time I hope that the when there are the floods or surplus waters in Ganga they will be taken down and some of the rivers which are empty today, such as the

[Dr. K. L. Rao]

Vaigai, will be flowing with water but that will be in the next century.

Now, I would turn to rural electrification. Hon. Members have pointed out the necessity for taking up rural electrification and said that the work done so far has not been really up to the mark. They say that only 67,000 villages have been electrified so far out of 5,70,000 villages and it is a very small quantum, and they asked how it is that during all these years we have done only very little, out of the 5,70,000 villages. They said that it will take many more years before all these villages are electrified. I would submit that there is a paradox in this. The paradox is that out of 5,70,000 villages 3,50,000 are only small villages with a population of less than 500 each. It is only 2 lakh odd villages which have got a higher population of about 2,000 or so each which have to be electrified first. Of course, there are some villages with a population of 500 each which have also been electrified, but there are only 2 lakh odd villages wich have got a population of more than about 2,000. The result is that today, by electrifying 67 000 villages, possibly we have served nearly 30 per cent of the rural population. It is not to be viewed as a proportion of 67,000 versus 5,70,000. Nearly one-third of our rural population has been served by giving them rural electrification, but that is no real satisfaction. I can appreciate the anxiety of the hon. Members that all the villages including those with a population of 500 or so should be electrified and be given the same amenities as are found in the cities. Therefore, while I am one with them in seeing that we should try to electrify as many villages as possible, at the same time, we should remember that what we have done is not insignificant in that we have electrified and served nearly one-third of the rural population and we are trying to extend the facility in a more accelerated way.

Many hon. Members have said that by 2nd October, 1970 the completion of the Gandhi Centenary Year, we are aiming at electrifying one lakh villages, but then we have been able to electrify only 67,000 villages so far. If every year we are going to add 9,000 villages, that will come to 80,000 in all. We can put in another 14,000 villages which means that 67,000 plus 14,000 will make up a little over 80,000 villages. And yet 20,000 villages will still remain, and so, they asked what we are going to do about them. I still feel that if we want to practise what Mahatma Gandhi preached, we can achieve our object. Gandhiji said that Swaraj in India means Swaraj in the villages, and unless Swaraj in the villages is attained there is no Swaraj for India as a whole. I feel that is entirely correct. It means that it is our duty, it is the duty of the people, it is the duty of the States and it is the duty of the Centre, it is the duty of all of us, to see that these 20,000 villages are also electrified so that we will be able to say that on 2nd October, 1970, we have electrified one lakh villages in all. It will be paying a tribute to the memory of that great man who led us to freedom and liberty.

Therefore, I still feel that we will be able to do it ; I do not want to give up the feeling and say that we cannot do it. It is quite possible, physically possible, and all that we want is more money and more contribution from the people. The States may be able to give money ; if the Centre cannot give more money, if the hon. Finance Minister is not able to give more money, we may try to get a little more contribution from the people as a whole, and see that one lakh villages are electrified, and that it self will electrify the whole nation, and remind us of Gandhiji's wish. That is the direction in which we should aim at.

Hon. Members have spoken about the inter-water disputes. I am sorry and I plead guilty in this regard in the sense that I had always hoped during the last few years that we should be able to solve this problem by negotiation. I sincerely believe that negotiations are the best and that adjudication, leaving the problem for adjudication, could create bitterness among the contending parties to the disputes. But it was found that the situation in the States was such that it is no longer possible to settle the disputes by negotiation, and that we should take action under the Inter-State Water Disputes Act. They said that the

Krishna-Godavari dispute could be decided under the Act, but at the last moment, a very senior leader of the nation said, "Why not you try once again by negotiation" ? And that is what is going to be done on the 3rd April, in another two days, they are going to make another attempt. If that fails, naturally, it will go to the tribunal.

In regard to Narmada, I quite appreciate what the Gujarat Government said. They have been pressing that the tribunal must be resorted to. It was felt that we have been waiting for six years and the Narmada waters were going to waste. We have a lot of work to do and have a lot of land to be irrigated. Therefore, this should be referred to the tribunal. I have always felt, why not make one more attempt ? I wrote to the previous Chief Minister and a reply was received that a new ministry was going to come in Madhya Pradesh. That was about 20 to 30 days ago and that I should contact the new ministry after it is formed. I am waiting for the new ministry to come in M. P. and for the portfolios to be setteld. Then we will make a last attempt. If we fail in that, the court, etc. is always there.

AN HON. MEMBER : Fix a time-limit for that.

DR. K. L. RAO : I have already spoken to the Chief Minister and he said, let the new ministry be formed. As soon as the new ministry is formed, we will contact them. If they think that. that approach is possible and useful, we will procced. Otherwise, we will go in for adjudication.

SHRI S. M. KRISHNA : What about twin tribunals for Krishna-Godavari ?

DR. K. L. RAO : About the tribunals, I do not mind giving the facts. I am only a humble person. but I have been attacked by the Mysore Government, the Mysore Assembly...

SHRI S. M. KRISHNA : By the Mysore Pradesh Congress Committee and the opposition members also.

DR. K. L. RAO : I have been attacked by all of them. For the information of the hon. member, I may tell him that anybody who runs the Government knows that the Ministry of Irrigation and Power has nothing to do with the interpretation of the Inter-State Water Dispute Act. They refer it to the Ministry of Law. The Ministry of Law gives its opinion and then it goes to the Cabinet. Then the Cabinet decides. That is the procedure. It has nothing to do with any one single individual. Even the suggestion does not come from any single individual. The same procedure was followed in that case. I do not want to say anything more about it. I have been abused wrongly. But I do not mind it. That is part of public life. I am only sorry for Mysore, because I have got the greatest respect for that State, which produced Sri Visveswarayya, from whom we have learnt many lessons and drawn inspiration.

I come to Hemavati project. The hon. member said, I am at war with Mysore.

SHRI S. M. KRISHNA : I said, war of nerves ; not war. Not yet at any rate.

DR. K. L. RAO : Hemavati is a river which is upstream of Krishnarajasagar and there are certain gauges. There is a very strict agreement between Mysore and Madras. When Mysore wanted to construct a project upstream, naturally Madras objected and Mysore has been replied. Of course, I am only doing my duty and there is no question of thanking me. I have gone out of the way, met both Chief Ministers, made them sit down together and I suggested a beautiful solution. Both of them accepted it. But when I send the comments for confirmation, the confirmation does not come. In the absence of confirmation, if we say that we clear the project, what will happen ? My hon. friend from Madras would not have let me off easily; he would have mounted guns on me. We have to be very cautious in these matters. In this particular case, we have got a very good solution by which it is possible to construct that project, provided certain precautions are taken and certain gauge levels are recorded. I have written to the Mysore Chief Minister for an immediate reply. Even Now I would appeal to Mysore to follow the understanding we arrived it,

[Dr. K. L. Rao]

so that Hemavati project can be taken up. Otherwise, in the absence of agreement between Madras and Mysore, to say that I should clear the project is really not a duty which you should ask me to do.

I have told the hon. Member some time before that an Irrigation Commission is over due. The last Irrigation Commission was set up some where in 1903. For the last 60 years no review of the whole affair has been done. Therefore, an Irrigation Commission is going to be set up which will look into the various stages of coordination. I am glad to submit that the Commission will be under the chairmanship of Shri A. P. Jain who had been our Minister of Agriculture before. It consists of Dr. Sen of the Planning Commission, two engineers-one from the north and one from the south and one agriculture expert. We hope that they will be able to give us some very sound advice on the various aspects of irrigation.

There is one other aspect that is worrying me. In the matter of electricity, after my visit to the United States I found that power production in this country is at a very high cost. The capital cost of power per kilowatt is Rs. 2000 in this country where as in the United States it is only Rs. 1000. The cost of generation of thermal power per unit is seven paise in this country where as in the United States it is only 4½ paise. Transmission loss in this country is anything like 16 percent where as in the United States it is only 8 per cent. Unless we are able to supply cheap power it will not be possible to build up the country. The only way to make a success of our nation building effort is by selling a very large amount of power at cheap price. Both are required and both are inter-related. If only you generate power on a large scale the price will come down. Therefore, we must take effective steps for it. For that reason we are setting up a technical committee with some of the friends from America and some of the experts here to go into the various aspects covering generation of power so that we will be able to achieve reduction in the cost that we are now having. I only hope that this committee will complete its labour early and give us a report so that we will be able to adpot some effective economic measures. In a few days the personnel of the committee will be announced.

There are a large number of engineers in our country, both experienced and youngsters. It is high time that we go out of the country. There are many countries where they require the services of engineers in the field of irrigation and power. It is high time that we take advantage of UNO, the Asian Bank and other such bodies. The other day I had been to Afghanistan There I saw a work. which probably would have been done in India-just an investigation work-for anything like Rs. 3 lakhs, being let out to a French firm for something like Rs. 1 crore. We can do it much cheaper than that. We, therefore, want to compete in the international field for designs and investigations. We are now organising a company known as Water and Power Development International so that we can try to get work and experience in outside bodies.

I now come to some of the specific projects that were mentioned. Shri Gowder mentioned about Avinashi, Palladam and Coimbatore area. No doubt those areas are really bereft of water completely. They are very dry areas. But there again there is the same problem as in the case of Madras and Mysore. Here it is Madras and Kerala. Unless there is understanding between the people of those two States it is not possible for us to take any steps which will put one State at an advantage over the other. We are going to hold a meeting with the Chief Ministers of Madras and Kerala, discuss the Lower Bhawani valley and the Periyakulam Aliyar System and arrive at some settlement. Once that is done, it will be possible to know how much water can be used in Kerala area and how much water can be used in Madras area. Even that does not solve the problem. In the Madras area there is internal trouble : there is the question of the Lower Bhavani which is already there and these areas which will be coming, there will be trouble about that, That has

to be sorted out. But I appreciate that Avinashi area does require some project.

17 hrs.

The hon. Member, Shri Gowder, referred to soil conservation in Ooty. This is dealt with by the Ministry of Agriculture. He referred to soil terracing and said that because of this soil has gone and pebbles and other things are coming up and the whole land is being wasted. I do not know how it has come about. If there is only a thin soil cover, we do not allow terracing to be done. If it is done, it is injurious to the area. So, I would request my colleague, the hon. Minister of food and Agriculture, to send one of his officers to look into this.

Then the hon. Member, Shri Patil, referred to a large number of projects in Maharashtra which are awaiting sanction of the Centre. I would again like to submit that during the last five or six years in terms of cost the number of projects sanctioned for Maharashtra come to one-third of the total for the country. They will irrigate 20 lakhs acres of land. At the moment, in Maharashtra the major and medium projects irrigate only 12 lakhs acres of land. The sanctioned projects will add another 20 lakhs acres of land. So, what is require dis implementation of those projects which were sanctioned five years back. They have to find money for it ; they are rich people and they can do it. They must find the money for the implementation of the projects and make a beginning. The irrigation scarcity can be solved, not by sanctioning of projects but by implementation of projects. If sanctioning of projects will solve the problem, there are Rs. 1,000 crores worth of projects waiting sanction in the office of the CWPC. But that does not solve the problem. What solves the problem is actual implementation of the projects which have been sanctioned. If all the projects of Maharashtra which have been sanctioned are implemented in the course of next few years, then more projects can be sanctioned. So, to make a grievance of the projects not being sanctioned is really not fair.

Another hon. Member referred to Koppili project in Assam. I think the idea of the hon. Member is that this project will serve as an irrigation, flood control and power project. Unfortunately, the site on which we have spent quite a lot of money and a number of years of investigation did not prove helpful. It had limestone and heavy cavities. So, the Assam Government have now sent another project. But that is only purely for power generation, and that too only a small amount of power. That project is not designed for irrigation or flood control. I had been to Nowgong area and what is wanted in that area is flood prevention and irrigation. For that you require a storage tank for the detention of the Koppili water. I have asked the officers to investigate other sites specially for this purpose, not to go to the limestone area but lower down in order to store up water. I hope they will be doing that.

The hon. lady Member referred to Barak project in Assam. It is a very slow moving river but with a very heavy amount of water. It catches the highest rainfall of the world, Chirapunji rainfall waters, and it causes heavy floods in the Cachar district of Assam. We have done investigation of this problem and we have been able to suggest a scheme. That scheme consists of constructing a reservoir for holding back peak waters so that there will be only moderate floods and the floods will be much less. But, unfortunately, it submerges areas in Manipur State and, therefore, it is a question of getting into correspondence with the Manipur Chief Minister. It is a question again of finding out how best to rehabilitate those people and where they can be rehabilitated. I think, both Shri Laskar and the hon. lady Member must try to use their good offices also in impressing upon the Manipur Chief Minister to do something in the matter. It is a very difficult problem.

SHRIMATI JYOTSNA CHANDA : Is not the Government negotiating with the Manipur Government ?

DR. K. L. RAO : We are doing that but one voice alone will not be sufficient in these matters and that too when they are

[Dr. K. L. Rao]

supposed to be the Manipur Nagas. It is a difficult problem.

SHRIMATI JYOTSNA CHANDA : The Central Government must take the responsibility.

DR. K. L. RAO : That we are doing.

The hon. Member, Shri Ganga Reddy, said that the Pochampad Project should be completed. I entirely agree with him. The Pochampad project was sanctioned many years back and it was started nearly ten years ago. It is very high time that it should have been completed. The only trouble was that that area is a part of Andhra Pradesh and it is another major project. The policy of the Government of India was to finance fully only one major project in a State and that is how this project suffered. So far out of Rs. 40 crores, Rs. 11 crores have been spent on this and I find that in the Fourth Plan they have made allocation for it. I hope, it will be accelerated. It is a very simple project and 6 lakh acres can be brought under irrigation quite simply from the Godavari River. I will take some further steps to see that the utilisation of the waters will begin much earlier, probably in another one or two years.

Then, Shri Ganga Reddy made another point about the north canal. At the moment there is only the south canal. He said with great force that a large number of villages are going to be submerged and that those people must be given rehabilitation by having the north canal. It is entirely correct. In fact, nowadays the most important point that we have got to look after is the rehabilitation of the people who are displaced in these reservoirs. That is growing more and more important and more and more difficult. Therefore I will entirely agree that the north canal must be constructed simultaneously and I will take it up with the Andhra Pradesh Government.

Then he mentioned the Swarna Project also. It is another unfortunate project. It started in the Second Plan and nearly Rs. ½ crores was spent on it. The project would have been completed but for the fact that it was submerging some 450 acres in Maharashtra and the Maharashtra Government objected. There the matter rests. This again is a matter which has got to be dealt with very delicately and I hope that we should be able to do something in the matter and see that the Swarna Project comes into use.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : How many decades will it take to complete the Tungabhadra high-level canal, second phase, and the Srisailam hydro-electric project ?

DR. K. L. RAO : I have got a lot of projects to deal with. I have got ahead of it 30 questions to answer.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Since you are dealing with Andhra Pradesh, you could as well give this information.

17.09 hrs

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

Sir, I want the hon. Minister to give some information. If he has no information, he can say so but he cannot skip over my question. I want specific information with regard to the completion of the Srikakulam hydro-electric project and the Tungabhadra high-level canal, second stage, since they have been included and are under execution. What time will they take to complete?

DR. K. L. RAO : I wish, I am able to answer that question. I have got the information also; it is not that I do not have it. But the hon. Deputy-Speaker had allowed a number of Members to ask questions and there are 30 questions already put to me. This is the thirty-first question. They will say, because I am from Andhra, I am giving preference to Andhra. I do not think I am entitled to do that.

Some hon. Members from U. P. said that no project has been taken up in U. P. and that irrigation has got to be built up in Uttar Pradesh. One hon. Member speci-

fically asked about the Sarjoo project also. I want to submit that we have taken a very nice project in U. P., harnessing, for the first time, the waters of Ghaghra river and when that is expected to be completed in five years, we will be able to irrigate all the area between Ghaghra and Ganga which is practically now a very backward area in Uttar Pradesh. Nearly a very large extensive area of that backward area will be supplied water. This is one of the most backward areas of our country and everyone would like that there is rapid progress in the completion of this project.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार के लिये कोई मेजर स्कीम और कोसी तथा गण्डक के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं....

MR. SPEAKER : The Minister has said that he will communicate to you. I was hearing your questions also. The Minister has promised that he will write to you about those points raised.

श्री रामावतार शास्त्री : उन स्कीमों के बारे में इन को जरूर कुछ बोलना चाहिये ।

DR. K. L. RAO : About the Rajasthan Canal, it deserves the attention of the House and it deserves the attention of the nation because the temporary provisions for supply of water to Pakistan under the Indus Treaty is coming to close by March, 1970. All the waters of the eastern rivers belong to India, Ravi, Beas and Sutlej, and we should utilise them. We are spending a lot of money on it. The amount of money that is required for the completion of the project should be given. That is also what the Planning Commission is trying to do. The only difficulty is that they are insisting it should be within the State Plan. If it is within the State Plan, it will not be possible to adjust it. That is where the difficulty is. We have got to find a way out. I have already drawn the attention of the Deputy Prime Minister and the Finance Minister to this aspect. We are taking necessary steps. I am pretty certain that the importance of the project itself will accelerate the progress of the project. I am certain that the project will be completed much earlier than what we are thinking.

Many hon. Members from Bihar spoke about various projects. There is not much time at my disposal. I will, however, deal with one question and that is about the electricity rates. One hon. Member said that the electricity rate has not been decreased and that what we are saying is not correct. What I want to submit is that, actually, as a result of Central intervention, the electricity rate has been brought down to uniform level in Bihar. It is 15 p. a unit. If the amount of power that is going to be consumed is more, it will be 12 p. a unit. Even if it is 15p. the Government has offered the subsidy of 50 per cent provided the State gives another 50 per cent. If the State is not able to find it acceptable, if they have not done it, we cannot help it. Anyway, the rates are much reduced now. What actually is required in Bihar is that the power-lines must be spread out more. The power is also there. What we want is that power-lines should be spread out specially in north Bihar which is got to be fed with more power-lines.

There are a large number of questions relating to various projects of other States. I only feel guilty that I have not been able to deal with them because of lack of time. I would submit that I will write to the hon. Members, answer their questions and send them the information.

I once again, thank the hon. House...

श्री महाराज सिंह भारती : जरा पिकिंग-पीरियड के लिये भी बतलाइये कि बिजली कहां से देंगे ।

DR. K. L. RAO : I shall discuss it with the hon. Member.

I would submit that, in respect of the Ministry of Irrigation and Power, the House has been very helpful. I only wish that the House keeps up its enthusiasm for these two subjects, so that it will be possible for us to get more funds and we may be able to do justice to the country.

MR. SPEAKER : I shall now put all the Cut Motions which have been moved together to the vote of the House.

All the Cut Motions were put and negatived.

MR. SPEAKER : The question is :

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 65 to 67, 123 and 124, relating to the Ministry of Irrigation & Power."

The motion was adopted.

[*The Motions for Demands for grants which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below-Ed.*]

Demand No. 65-Ministry of Irrigation and Power.

"That a sum not exceeding Rs. 32,58,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1970, in respect of 'Ministry of Irrigation and Power.' "

Demand No. 66-Multi-purpose River Schemes.

"That a sum not exceeding Rs. 1,81,21,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1970, in respect of 'Multi-purpose River Schemes.' "

Demand No- 67-Other Revenue expenditure of the Ministry of Irrigation and Power.

"That a sum not exceeding Rs. 7,86,52,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1970, in respect of 'Other Revenue expenditure of the Ministry of Irrigation and Power.' "

Demand No. 123-Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes.

"That a sum not exceeding Rs. 17,08,80,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1970, in respect of 'Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes.' "

Demand No. 124-Other Capital Outlay of the Ministry of Irrigation and Power.

"That a sum not exceeding Rs. 20,11,53,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1970, in respect of 'Other Capital Outlay of the Ministry of Irrigation and Power.' "

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : What about Haryana ? No money has been sanctioned.....

MR. SPEAKER : He will write to you about Haryana.

---

17. 17 hrs.

DISCUSSION *RE* : RECENT DEVELOPMENTS IN TELENGANA AND OTHER AREAS OF ANDHRA PRADESH

MR. SPEAKER : Before we take up the discussion on the Telengana and other areas of Andhra Pradesh, I would like to make an appeal to the hon. members. The situation there is already explosive. It is also a fact that the Telengana area was not done due justice in the last twelve years. There is no point in blaming any one individual there. Therefore, any suggestion which will help consolidation will be very useful. I am sure that the feelings of the Telengana people and the injustice done to